● वर्ष-2
● अंक-285
रायपुर, शुक्रवार 21 जुलाई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

samacharpacheesa@gmail.com

।। संगछध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

मणिपुर प्रकरण: हैवान की सामने आई तस्वीर

यौन उत्पीड़न करने वाली भीड़ में शामिल मुख्य अपराधी का पर्दाफाश

इंफाल । मणिपुर इन दिनों जातीय हिंसा की चपेट में है, लेकिन अब एक वीडियो को लेकर मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में तनाव फैल गया है जिसमें दो महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह वीडियो चार मई का है और दोनों महिलाएं कुकी समुदाय से हैं, वहीं जो लोग महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमा रहे हैं वो सभी मैतई समुदाय से हैं। मामले में अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आदिवासी संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मणिपुर से एक वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक बवाल जबरदस्त तरीके से जारी है। इसकी गूंज आज संसद में भी देखी गई। हालांकि, प्रधानमंत्री ने वायरल वीडियो को लेकर अपना विरोध जाहिर किया और कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल पूरे मामले को लेकर भाजपा पर हमलावर हैं। इन सबके बीच भाजपा की ओर से पलटवार किया गया है। भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि संवेदनशील मुद्दों पर कांग्रेस सिर्फ राजनीति करना जानती है।

इधर, मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाने और उनका यौन उत्पीड़न करने वाली भीड़ में शामिल मुख्य अपराधी का पर्दाफाश हो गया है। पेची अवांग लीकाई के रहने वाले 32 वर्षीय हुइरेम हेरोदास मैतेई को मणिपुर पुलिस के एक अभियान में गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया

गया। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा की गई तस्वीरों में गिरफ्तार आरोपी को हरे रंग की शर्ट पहने हुए दिखाया गया है, जो वायरल वीडियो के स्क्रीनग्रैब में भी देखा गया है।

पुलिस ने क्या कहा

मणिपुर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि आने वाले घंटों में और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि दर्ज एफआईआर में बलात्कार और हत्या की धाराएं जोड़ी गई हैं। 4 मई को 800-1,000 उपद्रवियों की सशस्त्र भीड़ द्वारा कुकी महिलाओं को निर्वस्त्र करने और उनके साथ यौन उत्पीड़न करने के भयानक वायरल वीडियो ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर आक्रोश फैलाया है। यह घटना 4 मई को बी फीनोम गांव में हुई थी। एफआईआर के मुताबिक, पांच लोगों का एक परिवार भीड़ से बचने के लिए जंगल में भाग गया था, जिसने उनके गांव पर हमला किया था, लूटपाट की थी और घरों को जला दिया था। पुलिस ने उन्हें बचाया।

विपक्षी शासित राज्यों में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर चुप्पी

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मणिपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को राजनीतिक रूप से न देखे जाने व इस पार्क सरकार द्वारा चर्चा के लिए तैयार होने के बावजूद विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को भटकाने व राजनैतिक रंग देने की बात कही है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन संवाददाताओं से बात करते हुए ठाकुर ने कहा, मणिपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेहद कड़ा संदेश देते हुए दोषियों को सजा देने की बात कही है, दु:ख प्रकट किया है और राज्य सरकारों से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर नकेल कसने की बात कही है मगर विपक्ष, खा़सकर कांग्रेस इस पर चर्चा क्यों नहीं चाहता? विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर ये लोग चुप्पी क्यों साध लेते हैं। ठाकुर ने आगे कहा, हम इस गंभीर मुद्दे पर संसद में चर्चा हेतु तैयार थे पर विपक्ष इससे भाग रहा है। उनकी क्या मजबूरी है कि वे चर्चा नहीं करना चाहते? इसका एकमात्र कारण यह है की विपक्ष महिलाओं को राजनीतिक टूल मानकर इस पर राजनीति करता है।

संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करती है कांग्रेस: रविशंकर प्रसाद

भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन विपक्षी मामला तो उठाते हैं लेकिन चर्चा को तैयार नहीं होते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि हम पूरे आश्वासन और विश्वास के साथ दोहराना चाहेंगे कि मोदी सरकार भारत की महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जो घटना मणिपुर की है वह दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सभी आहत हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है, कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया है और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में देश में जागृति फैलाने की बात की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है कि संवेदनशील मुद्दों पर आपका दृष्टिकोण क्या है। क्या आप वास्तविक चर्चा चाहते हैं या आप चाहते हैं कि जिन नियमों के तहत चर्चा होगी, उन पर आपके अहंकार का असर हो? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में हम इस पर बहस चाहते थे, क्योंकि ये हमारे लिए गंभीर विषय है। मोदी सरकार देश की बहन-बेटियों की इज्जत के बारे में बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले हर सदन से पहले एक गुब्बारा छोड़ते हैं और फिर बहस से भाग जाते हैं। आप सभी को याद होगा...वो पेगासस की बात लेकर आए थे, सरकार की ओर से जवाब दिया गया, कहा- सुप्रीम कोर्ट से इन्क्वायरी होनी चाहिए और जब इन्क्वायरी हुई तो राहुल गांधी ने अपना ही फोन नहीं दिया। कांग्रेस के इन कुकृत्यों को याद किया जाना चाहिए।

इन दिनों

✍ अमित शर्मा

क्या इंडिया नाम रखकर विपक्ष ने तोड़ा कानून

विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम देकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। इस नाम को भारत के आधिकारिक नाम का दुरुपयोग बताते हुए दिल्ली के बाराखंबा थाने में 26 विपक्षी दलों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लेकिन कानूनविदों की राय है कि चूंकि इंडिया शब्द को किसी संस्था या राजनीतिक दल के आधिकारिक नाम के तौर पर उपयोग नहीं किया गया है, इससे कोई आर्थिक लाभ लेने की कोशिश नहीं की गई है, और इसका कहीं रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया जाना है, सर्वोच्च न्यायालय या चुनाव आयोग में इसे गैर कानूनी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, यह किसी संस्था (यहां भारत देश) के नाम का उपयोग कर लोगों को भ्रम में डालने का मामला बन सकता है। भारतीय दंड संहिता के आधार पर यह गैरकानूनी और दंडात्मक है। इस मामले में इन राजनीतिक दलों पर कार्रवाई की जा सकती है। इन राजनीतिक दलों के द्वारा इंडिया की ओर से सोशल मीडिया में किए गए पोस्ट साक्ष्य के रूप में उपयोग किये जा सकते हैं। विपक्षी दलों के द्वारा इंडिया शब्द का उपयोग किसी भी तरह गैरकानूनी नहीं है। इस नाम का न तो कहीं रजिस्ट्रेशन कराया गया है, और न ही इससे कोई आर्थिक लाभ लेने की कोशिश की गई है, ऐसे में इसे अपराध नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि लोग अपना या अपनी संस्था का नाम भारत या हिंदुस्तानी रख लेते हैं। लेकिन यह अपराध नहीं है। वहीं, सर्वोच्च न्यायालय के वकील संजीव उनियाल ने कहा कि एंब्लेम एक्ट में यह साफ कहा गया है कि राज्य के नाम या प्रतीकों का किसी व्यक्ति या निजी संस्था के द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे में विपक्षी दलों का इंडिया का नाम उपयोग करना गलत है। सर्वोच्च न्यायालय भी इस मामले को सही नहीं कह सकता। भारतीय दंड संहिता में किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था का नाम का छद्म रूप से उपयोग करना दंडनीय अपराध है। इससे लोगों को भ्रम हो सकता है और वे किसी बहकावे में आ सकते हैं। ऐसे में इसे अपराध माना गया है। जिस तरह किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपना या अपनी संस्था का नाम सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग या नीति आयोग रखने की छूट नहीं मिल सकती क्योंकि इससे लोगों को भ्रम हो सकता है, और इसका दुरुपयोग हो सकता है, उसी प्रकार इंडिया या भारत रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि, इस संदर्भ में इंडिया की हर स्पेलिंग के बाद पूर्ण विराम का उपयोग किया गया है, इसे पूरी तरह इंडिया के नाम का दुरुपयोग नहीं कहा जा सकता। इसका एक संस्था या राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत न कराना भी इसके बचाव का एक कारण हो सकता है। लेकिन इस मामले में छद्म नाम का उपयोग कर लोगों को भ्रमित करने का मामला बन सकता है और इस कारण विपक्षी दलों की परेशानी बढ़ सकती है।

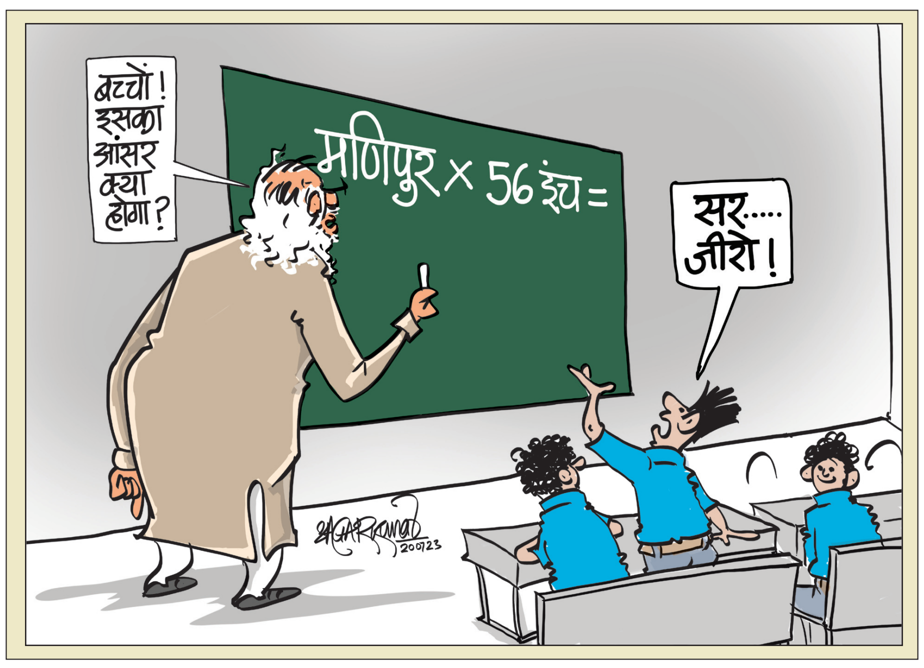

रायपुर में मुगलिया शासन, मंत्री की नही चलती : बृजमोहन

रायपुर। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर नगर निगम को पांच वर्ष में आवंटित राशि, शारदा चौक से तात्या पारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण सहित विकास कार्यों एवं भ्रष्टाचार का मामला विधानसभा में उठाया। उन्होंने सीधे-सीधे कहा कि नगर निगम में मुख्यमंत्री का नहीं, मंत्री का नहीं चल रही है। रायपुर नगर निगम में मुगलिया शासन चल रहा है। शासन द्वारा जारी 1,327 करोड़ 49 लाख 32 रुपए कहां जा रहा है इन पैसों का सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। श्री अग्रवाल आज विधानसभा में रायपुर नगर निगम को पांच साल में मिली राशि, शारदा चौक से तात्यापारा चौक तक सड़क चौड़ीकरण का मामला उठाते हुए मंत्री से पूछा कि रायपुर नगर निगम को 5 सालों में कितनी राशि

उपलब्ध कराई गई है? वर्षवार विधानसभा वार बताएं। स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण है, कितने अपूर्ण? रायपुर नगर निगम को केंद्रीय योजनाओं की कितनी राशि प्राप्त हुई है? उन योजनाओं में कितने का कितने कार्य पूर्ण कितने अपूर्ण है? श्री अग्रवाल ने कहा कि राजधानी की स्थिति बहुत खराब है। रायपुर गड्ढों से भरा हुआ है। धूल से भरा हुआ है। बरसात में पानी भर रहा है। जिस काम के लिए पैसा मिल रहा है, उस काम में खर्च नहीं होता। पैसे का खुलकर दुरुपयोग होता है, और क्या रायपुर में बढ़िया शासन चल रहा हैं? श्री अग्रवाल ने कहा कि राजधानी की इतनी बुरी हालत पिछले साढ़े 4 साल में हुई है। सड़कों के गड्ढों से लोग परेशान हैं। लोग गड्ढों में बेशरम का पेड़ लगा रहे हैं। आप पैसा देते हैं उन पैसों को लोग खा रहे हैं। वह पैसा लोगों के जेब में जा रहा है। रायपुर नगर निगम ऐसा नगर निगम है जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मंत्री का शासन नहीं मुगलिया शासन चल रहा है और उस शासन में सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है। उनका राज चल रहा है वे जैसा चाहे वैसा करें। जिसको ठेका देना हो दे। आपको मालूम है मैंने इस विधानसभा में पूछा तो पता चला कि तेलीबांधा से लेकर वीआईपी रोड पर किए गए सड़क सोदर्यीकरण का टेंडर नहीं हुआ है। वह जादू में बन गया। ढाई करोड़ के टेंडर को 20-20 लाख में किया गया। मंत्री जी आपने विधानसभा में जवाब में कहा था कि उनका टेंडर किया है। एनएचआई से हमें परमिशन नहीं मिला। फिर काम कैसे हो गया? तो जादू से काम होने लगा क्या? श्री अग्रवाल ने शारदा चौक से तात्या पारा तक सड़क चौड़ीकरण का मामला उठाते हुए कहा कि इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए पिछले साढ़े 4 सालों से मुख्यमंत्री जी लगातार हर साल सदन में आश्वासन दे रहे हैं। घोषणा किया है पर आज तक उस सड़क के निर्माण के लिए पैसा जारी नहीं किया गया।

>> विधानसभा समाचार पृष्ठ 6 पर

प्रमुख समाचार

साक्ष्य गढ़ने के मामले में सीतलवाड की अर्जी खारिज

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड की जमानत याचिका की अनुमति दिए जाने के एक दिन बाद गुजरात के अहमदाबाद की एक शहर सत्र अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में उच्च सरकारी अधिकारियों को फंसाने के

लिए सबूत गढ़ने के आरोप के संबंध में उनके आरोपमुक्त करने के आवेदन को खारिज कर दिया। सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट, अहमदाबाद के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश एआर पटेल ने सीतलवाड द्वारा दायर आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि प्रथम दृष्टया मामला बनाया जा सकता है। उसने गुजरात राज्य द्वारा सरकारी अधिकारियों को गलत तरीके से फंसाने के लिए सबूत गढ़ने और गवाहों को प्रशिक्षित करने के उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के सामने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी है। अपने डिस्चार्ज आवेदन में, उसने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि कोई भी आधार मौजूद नहीं है जो उसे उन अपराधों से जोड़ता हो जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया है। हालाँकि, इस तर्क को न्यायाधीश का समर्थन नहीं मिला, जिन्होंने सीतलवाड के खिलाफ फैसला सुनाया।

उप-सभापतियों के पैनल में 50 फीसदी महिला सदस्य नामित

नई दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए राज्यसभा में उप-सभापतियों के पैनल में 50 फीसदी महिला सदस्यों को नामित किया है। मानसून सत्र से पहले पुनर्गठित पैनल में कुल आठ नाम हैं, जिसमें से आधी महिलाएं हैं। राज्यसभा के इतिहास में यह पहला मौका है कि उप-सभापतियों के पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहीं इस फैसले से राज्यसभा में पहली बार लैंगिक समानता होगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को उप-सभापतियों के पैनल में चार महिला सांसदों के नामों की घोषणा की जिनमें नागालैंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला एस. फांगनोन कोन्याक, पद्म श्री पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध एथलीट पीटी उषा, फौजिया खान और सुलाता देव हैं। वह अप्रैल, 2022 में नागालैंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला हैं। वह परिवहन, पर्यटन और संस्कृति समिति, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की सलाहकार समिति, महिला सशक्तिकरण समिति, सदन समिति और पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य संस्थान की गवर्निंग काउंसिल और चिकित्सा विज्ञान, शिलांग की सदस्य हैं।

ज्योतिरादित्य सिंधिया के गृह क्षेत्र प्रियंका वाद्रा करेंगी रैली

भोपाल। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस के अभियान को मजबूती देने के लिए पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाद्रा शुक्रवार को महत्वपूर्ण ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में एक

सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगी। यह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गृह क्षेत्र है। इसे सिंधिया के गढ़ के रूप में भी देखा जाता है। प्रियंका गांधी ने जून में जबलपुर में एक रैली के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभियान की शुरुआत की थी और राज्य की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की सहायता सहित पार्टी के पांच वादों की घोषणा की थी। इस साल की शुरुआत में कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत में प्रियंका गांधी के अभियान और कांग्रेस द्वारा किए गए पांच वादों की अहम भूमिका देखी जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो भाजपा में जाने से पहले प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव थे, गुना से पूर्व सांसद हैं और ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में उनकी पकड़ है। सिंधिया को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बेहद करीबी माना जा था।

बृजभूषण को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने दी सशर्त जमानत

नईदिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कई पहलवानों की शिकायतों के आधार पर दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और

महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को नियमित जमानत दे दी है। कोर्ट की ओर से सशर्त जमानत दी गई है। कोर्ट ने कहा कि हमने कुछ शर्तें लगाई हैं। आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। वह अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। कृपया सुनिश्चित करें कि सभी शर्तों का ईमानदारी से पालन किया जाए। बृज भूषण को 25000 रुपये का मुचलका भरने पर जमानत मिलेगी। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। इससे पहले न्यायाधीश ने आरोपी और अभियोजन पक्ष के वकीलों के साथ-साथ शिकायतकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि आरोपियों पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए।

महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन से 13 लोगों की मौत

मुंबई। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में गुरुवार सुबह हुए भूस्खलन से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिससे लगभग 48 परिवार प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दुखद घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों के लिए 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। उन्होंने यह भी कहा कि घायलों के इलाज का खर्च महाराष्ट्र सरकार उठाएगी। इसके अलावा, जिस पहाड़ पर भूस्खलन हुआ था, उसकी चोटी तक पहुंचने के लिए विशेषज्ञ ट्रैकरों को बुलाया गया है। भूस्खलन में लगभग 46 घर प्रभावित हुए और 20 से अधिक मिट्टी में डूब गए हैं। इंडिया टुडे से बात करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि ज्यादातर लोगों की मौत इसलिए हुई क्योंकि जब भूस्खलन हुआ तो वे सो रहे थे और उन्हें खुद को बचाने का मौका नहीं मिला। कुछ बच्चे बेहतर मोबाइल नेटवर्क के लिए गेम खेलने के लिए गांव से बाहर गए थे। वे सबसे पहले भूस्खलन को नोटिस करने वाले थे और कुछ ग्रामीणों को सचेत करने में कामयाब रहे। एनडीआरएफ ने कहा कि दो टीमें मौके पर पहुंचीं और तलाश एवं बचाव अभियान चलाया. रायगढ़ में खालापुर तहसील के इरशालवाड़ी गांव में भूस्खलन हुआ, जिससे 48 परिवार प्रभावित हुए।

अगले साल खुलेंगे मायावती के सियासी पत्ते, यह 5 महीने तय करेंगे राह

आशीष तिवारी

बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने तय किया है कि उनका सियासी गठबंधन किसी से नहीं होगा। इसी के साथ बसपा आने वाले चुनावों में फिलहाल अकेले ही सियासी मैदान में नजर आएगी। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मायावती की किसी भी दल से गठबंधन न करने की योजना फिलहाल इस साल होने वाले वाले विधानसभा के चुनावों तक के लिए ही लग रही है। जैसे ही लोकसभा चुनाव से पहले के राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव खत्म होंगे, तो मायावती के असली सियासी पत्ते खुलने शुरू होंगे। फिर तय होगा कि मायावती राजनीतिक गठबंधन का रुख किस ओर जाएगा।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनावों से पहले जितने राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, वहां पर मायावती फिलहाल अकेले ही सियासी मैदान में नजर आएंगी। इसमें इस साल होने वाले चार राज्यों के चुनावों में राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना शामिल हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषण जटाशंकर सिंह कहते हैं कि जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं मायावती वहां पर अकेले चुनाव लड़कर अपनी पार्टी का सियासी कद आंकना चाह रही हैं। वह कहते हैं इन राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनावों के परिणाम और बहुजन समाज पार्टी को मिले वोट प्रतिशत से लोकसभा के चुनावों में होने वाले गठबंधन की दशा और दिशा मायावती तय करेंगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती ने जो भी योजना बनाई है, वह फिलहाल इस साल होने वाले चार राज्यों के विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर ही

बनती हुई नजर आ रही है।

दलित और मुस्लिम वोटों पर पकड़ से तय होगा पैमाना

राजनीतिक विश्लेषक जीडी शुक्ला का कहना है कि मायावती जिस तरीके से दलितों और मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ कर बड़ी सियासी चाल चल रही हैं, उससे तो यही लगता है कि यह चार राज्य उनके लिए सियासी प्रयोग की जमीन बनेगी। जीडी शुक्ला कहते हैं कि मायावती ने जो भी फॉर्मूला तय किया है, वह बहुत ही सोच समझकर और अपनी पार्टी को दोबारा जिंदा करने और मजबूत हैसियत में खड़ा करने के लिहाज से ही तय किया है। क्योंकि बीते कुछ चुनावों में बसपा पार्टी का सियासी ग्राफ जिस तरीके से नीचे गिरा है, उससे फिलहाल पार्टी किसी भी तरीके के गठबंधन से बचना चाह रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस साल होने वाले राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनावों में मायावती का वोट प्रतिशत जिस तरह से होगा, उसके आधार पर ही लोकसभा के चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि 2018 के इन चार राज्यों में हुए चुनावों में मायावती की पार्टी का वोट प्रतिशत एक से डेढ़ फीसदी के करीब ही रहा था। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि उनकी पार्टी इस बार राज्यों में ज्यादा वोट प्रतिशत के साथ विधानसभा की सीटें भी जीतेगी। सियासी जानकारों का कहना है कि मायावती इस बार दलित और मुस्लिम के कॉम्बिनेशन को सियासत में मजबूती के साथ सभी राज्यों में उतार रही है।

लोकसभा में बसपा की वजह से सपा का वोट हुआ था कम

लोकसभा के चुनावों का अगर आकलन किया जाए, तो पता चलता है कि मायावती के वोट प्रतिशत में फिलहाल इन चुनावों में तो सेंधमारी नहीं हो पाई है। आंकड़ों के मुताबिक 2014 में बहुजन समाज पार्टी की एक भी सीट नहीं थी। बावजूद इसके बसपा का वोट प्रतिशत 19.60 था। जबकि 2019 में देश के सबसे बड़े सियासी गठबंधन में से एक कहे जाने वाले सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ जब मायावती चुनाव में उतरीं, तो उन्हें 10 सीटें मिलीं, लेकिन वोट प्रतिशत 2014 के मुकाबले तकरीबन बराबर ही रहा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनावों के वोट प्रतिशत को अगर सियासी नजरिए से देखें, तो सबसे बड़ी सेंधमारी समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में हुई। 2014 में समाजवादी पार्टी को 22.20 वोट मिले थे। जबकि 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ हुए गठबंधन में महज 17.96 फीसदी ही वोट मिल सके। इस दौरान सपा की सीटें भी पांच ही रही। जबकि 2014 की तुलना में 2019 में भाजपा का वोट प्रतिशत 7 फ़ीसदी से ज्यादा हुआ, जो कि 49.6 फीसदी के पास है पहुंच गया था।

बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं में उत्साह, कांग्रेस से जुड़ रहे है लोग : मोहन लालवानी

■ सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व - विजय

नगरी। विगत दिनों राजीव भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी सप्तगिरिशंकर उल्का, जिला अध्यक्ष शरद लोहाना एवं उपस्थित वरिष्ठ नेताओं के द्वारा सरकार की योजनाओं से संबंधित पाम्पलेट का विमोचन किया गया. जिसका उद्देश्य लोगों के घर घर पहुंचकर सरकार की योजनाओं से अवगत करना है. जिसमे दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष मोहन लालवानी के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता लगातार बूथ स्तर के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ घर घर पहुंच कर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं. मंगलवार शाम दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष मोहन लालवानी, महापौर विजय देवांगन, मंडी अध्यक्ष ओंकार साहू, ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर देवांगन सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने ग्राम रत्नाबांधा और मुजगहन के चौक-चौराहों, हाट-बाजार एवं घरों में जाकर पम्पलेट का वितरण करते हुए. सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराया एवं योजनाओं से लाभ प्राप्त करने प्रेरित किया गया. दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष मोहन लालवानी ने बताया कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार लगातार हर वर्ग के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन हितैषी कार्य कर रही है. आगे कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ी परंपरा और संस्कृति को फिर से स्थापित कर रही है. प्रदेश में स्वाभिमान की एक नई लहर चली है. अपनी परंपराओं और संस्कृति को नई पीढ़ी से जोड़ा जा रहा है. जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में किया जा रहा प्रयास विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना जैसी कई योजनाएं प्रकृति की रक्षा के साथ किसानों की आय बढ़ाने में कारगर साबित हो रही हैं. राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से गांव के युवा रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ रहे हैं. एवं सरकार के कार्यों से लोग कांग्रेस से जुड़े हैं। महापौर विजय देवांगन ने कहां की

शासन द्वारा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने ग्राम पंचायत सहित विभिन्न उपक्रम स्थापित है. लेकिन इसे हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता और प्रभावी तरीके से लोगों के बीच पहुंचाते हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है की सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर लोगों को लाभ दिलवाए. जिला संगठन के द्वारा लगातार बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती के लिए कार्य किया जा रहा है. बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत शीर्ष नेतृत्व का बूथ स्तर पर पहुंचने से कार्यकर्ताओं में एक नया ऊर्जा का संचार हुआ और आज सरकार की योजना संबंधी पाम्पलेट वितरण के दौरान बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के द्वारा मजबूती के साथ लोगों के बीच पहुंचकर सरकार की योजनाओं को बताते हुए लाभ लेने प्रेरित किया गया। इस दौरान दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड अध्यक्ष मोहन लालवानी, महापौर विजय देवांगन, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष ओंकार साहू, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ईश्वर देवांगन, ब्लॉक महामंत्री अंबर चंद्राकर, ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण उपाध्यक्ष होमेंश्वर साहू, मुजगहन सरपंच चंद्रशेखर साहू, श्याम लाल साहू, भंवरलाल, ओम प्रकाश साहू, डेरहा राम साहू, भागवत साहू, मेहतर साहू, भुनेश्वर साहू, लिलेश्वर साहू, बलराम साहू, खूबचंद यादव, चैन सिंह ध्रुव, घनसु ध्रुव, रामबगस, लक्ष्मीनारायण, भीखम, विक्की, खिलेश साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

विधायक अपने क्षेत्र में नहीं बना पा रहे पुल व सड़क : भाजपा

कोरबा। ग्राम पोड़ी में कांग्रेस सरकार के कुशासन को उजागर करने के लिए तथा स्थानीय विधायक मोहित राम केरकेटा के निष्क्रियता को लेकर भाजपा ने विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व संसदीय सचिव लखन लाल देवांगन, पाली. तानाखार विधानसभा प्रभारी विजेंद्र शुक्ला, जिला मंत्री अजय जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष देवी सिह टेकाम, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री किरण मरकाम, पाली मंडल प्रभारी श्याम लाल मरावी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा प्रदेश मंत्री गोवर्धन सिंह, आदिवासी मोर्चा जिला महामंत्री विजय बहादुर जगत उपस्थित रहे।

मंचासीन वक्ताओं ने कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार में व्यस्त है। ग्रामीण जनों के छोट-.छोटे कार्यों के लिए जैसा वृद्धा पेंशन, वन अधिकार पट्टा, चाहे पटवारी के पास कार्य हो, तहसील में कार्य हो, इन सब कामों के लिए ग्रामीण जन दर-दर भटक रहे हैं। स्थानीय विधायक अपने ही क्षेत्र में सड़क एवं पुल नहीं बना पा रहे हैं। सड़क मार्ग पाली से पोड़ी होते हुए सिल्ली मार्ग तीन साल से भी अधिक समय गुजर जाने के बाद पूर्ण नहीं हो सका है। विधायक अपने क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तो पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या विकास कार्य करेंगें।

ऐसे विधायक को हटाने की जरूरत है। धरना प्रदर्शन में भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मुकेश, इंटरनेट मीडिया सहसंयोजक प्रभारी विभूति कश्यप, अध्यक्ष रोशन सिंह ठाकुर, पसान मंडल अध्यक्ष पवन सिंह, चैतमा मंडल अध्यक्ष कृष्णा यदु, वीरेंद्र मरकाम, रामनारायण उरेती, पुष्पराज ठाकुर, चंद्रमति, मंडल महासचिव विवेक कौशिक, कमल राज, मंडल मीडिया प्रभारी हरीश चावड़ा, कांता जायसवाल, राजेश सिंह ठाकुर, राजकुमार कंवर, भास्कर कश्यप, सुनील कश्यप, चैन दास समेत सभी मंडल से काफी संख्या में कार्यकर्ता, आमजन तथा महिलाएं शामिल रहीं।

भक्त माता कर्मा की खंडित हुई मूर्ति भाजपा ने लगाए घटिया निर्माण के आरोप

बेमेतरा। बेमेतरा जिला मुख्यालय में दुर्ग रोड में भक्त माता कर्मा की मूर्ति लगाई गई है। जिसे कर्मा चौक का नाम दिया है। लेकिन बुधवार रात मूर्ति को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद जिला मुख्यालय में हड़कंप मच गया ।इस मूर्ति के खंडित होते ही राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी ने मूर्ति निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस असामाजिक तत्वों की करतूत बताकर सिटी कोतवाली में केस दर्ज करने का आवेदन सौंपा है।

मूर्ति खंडित होने पर थाने में शिकायत

बेमेतरा के मां कर्मा माता चौक में स्थापित कर्मा माता की मूर्ति का हाथ टूट गया है। घटना बीती रात की बताई जा रही है। मूर्ति खंडित होने की जानकारी मिलने के बाद बेमेतरा नगर पालिका की अध्यक्ष शकुंतला साहू ने बेमेतरा सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर मामले की जांच कर शरारती तत्वों पर कार्रवाई की मांग की।

नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला साहू ने कहा कि हमें जानकारी मिली की भक्त माता कर्मा की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई है। आने पर पता चला की मूर्ति का हाथ टूटा हुआ है।जिसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की गई है।

घटिया निर्माण का लगाया आरोप- वहीं बीजेपी ने मूर्ति निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल होने का आरोप लगाया है।कर्मा माता मूर्ति खंडित होने की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष दीपेश साहू ने मूर्ति निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मामले में जांच की बात कही है।

वहीं शिकायत के बाद बेमेतरा सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अजय सिन्हा ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। लेकिन इस घटना में असामाजिक तत्वों का हाथ होने से फिलहाल इनकार किया है। उन्होंने कहा नगरपालिका अध्यक्ष ने मूर्ति को खंडित करने की शिकायत थाने में दी है। जिसकी जांच की जा रही है। मूर्ति क्यों खंडित हुई, कैसे हुआ इस बात की तस्दीक के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं।अभी तक असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी भी तरह की हरकत करने का मामला नहीं दिख रहा। जो भी नतीजा आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी।

आपको बता दें कि भक्त माता कर्मा की मूर्ति का अनावरण 14 जून को कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया था। इसी के साथ चौक का नाम भक्त माता कर्मा चौक पड़ा। लेकिन अब मूर्ति खंडित होने से स्थानीय लोगों में गुस्सा है।

भाजपाईयों ने विधायक निवास का किया घेराव

नगरी। भारतीय जनता पार्टी के सिहावा विधानसभा के कार्यकर्ता बजरंग चौक नगरी में धरना प्रदर्शन कर प्रमुख मांगों को लेकर जंगी आंदोलन किया। बजरंग चौक से जुलूस के रूप में पैदल मार्च कर विधायक निवास पहुंचकर विधायक निवास का घेराव किया। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे , किंतु भाजपाइयों ने दो बैरिकेट तोड़कर विधायक निवास तक पहुंचे। नहर नाली का विस्तार, किसानों को विद्युत कनेक्शन, कृषि महाविद्यालय की स्थापना, मगरलोड में 100 बिस्तर अस्पताल, कुकरेल बेलरगांव को ब्लॉक का दर्जा, चिटफंड कंपनी की राशि वापसी, पिछले 4.5 साल का बेरोजगारी भत्ता, नशीली दवाई, जुआ सट्टा बंद और अनेक प्रमुख मांगों को लेकर प्रर्दशन कर विधायक निवास का घेराव किया।

कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता पर्यावरण प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक गणेश शंकर मिश्रा (पूर्व कलेक्टर), भाजपा संगठन जिला प्रभारी नीलू शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार, राजा साहब कमलचंद्र भंजदेव रहे।

कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री श्रीमती पिंकी शिवराज शाह, पूर्व विधायक सिहावा श्रवण मरकाम, जिला महामंत्री प्रकाश बैस, जिला मंत्री राजेंद्र गोलछा, जिला मंत्री प्रेमलता नागवंशी, कार्यक्रम संयोजक नागेंद्र शुक्ला, सह संयोजक नरेश सिन्हा, विकल गुप्ता, हुमित लिमजा, मंडल प्रभारी रविशंकर दुबे, कमल डागा, दिनेश्वरी नेताम, महेंद्र नेताम, अराधना शुक्ला, अजय नाहटा, मंडल अध्यक्ष मोहन नाहटा, वामन साहू, अकबर कश्यप, विजय यदु, विधानसभा मीडिया प्रभारी रामगोपाल साहू, शत्रुघ्न साहू,राकेश चौबे, मनोहर मानिकपुरी, मोहन पुजारी, महेश गोटा,ईश्वरी नेताम, राजाराम मंडावी,चन्द्रशेखर अडिल, शशि ध्रुव, यशकरण पटेल, अशोक संचेती, निखिल साहू,मौर्यध्वज सेन,रामायण सिन्हा, अजय यादव, प्रतिमा देवांगन, कविता यादव, सुलोचना साहू, बलजीत छाबड़ा,शैलेंद्र साहू,चंद्रकला साहू सहित सिहावा विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।

एटीएम से छेड़छाड़ कर निकाले तीन लाख से ज्यादा, पकड़ाया कन्नौज गैंग

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस ने एटीएम से छेड़छाड़ कर ठगी करने वाले साइबर ठगों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कन्नौज गैंग के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने सहकारी बैंक के एटीएम से छेड़छाड़ कर तीन लाख रुपये से ज्यादा निकाले थे। इसके कुछ दिन बाद फिर से एटीएम से चोरी का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस बार पकड़े गए। इस मामले में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के शाखा प्रबंधक ने सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस ने बताया कि, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित की गरियाबंद शाखा में लगे एटीएम से 22 और 23 जून को छेड़खानी का 3.46 लाख रुपये निकाले गए थे। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने सायबर सेल की मदद से टीम का गठन किया। पुलिस अभी जांच कर रही थी कि 19 जुलाई की शाम एटीएम में घुसा एक व्यक्ति धोखाधड़ी कर रुपये निकालने का प्रयास कर रहा था। इस बार उसकी सारी हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर शहर में नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश शुरू की।

टीम ने जांच के दौरान बस स्टैंड के पास खड़े एक संदिग्ध को हिरासत में ले

लिया। पूछताछ में उसने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर एटीएम से फ्रॉड किए जाने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर दो अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया। उन्होंने राजिम और गरियाबंद में भी लगे एटीएम से धोखाधड़ी कर रुपये निकालने की बात बताई। इसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 31 डेबिट कार्ड और 5200 रुपये बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में कानपुर के केशी गांव निवासी गोविंद कुमार, कन्नौज के मौसमपुर मौरारा निवासी अभिषेक यादव और कन्नौज के ग्राम भड़हा निवासी राजेन्द्र सिंह शामिल है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। एटीएम से निकाली गई बाकी रकम को लेकर पुलिस की ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि एटीएम से फ्रॉड करने के बाद आरोपी बैंक लूटने की साजिश रच रहे थे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

चूहों का आतंक, देर रात बजने लगा बैंक का सायरन

जगदलपुर। बुधवार की देर रात को धरमपुरा स्थित एक बैंक में अचानक से तेज सायरन बजने लगा। जिसकी जानकारी आसपास के लोगों ने बोधघाट पुलिस के साथ ही कोतवाली पुलिस मौके पर आ पहुंची। जांच के दौरान पता चला कि चूहों की करामात ने पुलिस के साथ ही बैंक के अधिकारी कर्मचारियों को छकाया। मामले के बाद पुलिस से लेकर अधिकारियों ने राहत की सास ली। मामले के बारे में जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी अमित शुक्ला ने बताया कि धरमपुरा मार्ग पर अनुपमा चौक के नजदीक इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा में अचानक रात 11:30 बजे सायरन बजने लगा। सायरन की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे मोहल्ले के लोग जाग गए। कोतवाली और बोधघाट थाने से पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए। दरअसल, इस बात को लेकर आशंका थी कि कहीं किसी ने स्ट्रांग रूम में प्रवेश करने की कोशिश तो नहीं की है। पूरे बैंक परिसर की छानबीन के बाद पता चला कि इंफ्रारेड किरणों के बीच से होकर चूहे गुजर गए, जिसकी वजह से सायरन बजा था।

जैन समाज ने संत की हत्या के विरोध में निकाला मौन जुलूस

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। कनार्टक के बेलगावी के चिकोडी में हुई दिगंबर जैन संत की हत्या के विरोध में गुरुवार को छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में जैन समाज ने मौन जुलूस निकाला। जुलूस विभिन्न रास्तों से होता हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचा। जहां पर समाज के लोगों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए हत्यारो को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक, बेलगाम जिले में जैन मुनि कामकुमार नंदी महाराज लापता थे। भक्तों ने स्थानीय थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच शुरू की और एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की उसने जैन मुनि की हत्या करने और शव फेंकने की बात कबूल ली। पुलिस ने इस मामले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद से ही हिंदू और जैन समाज आंदोलित है। जैन समाज के साथ हिन्दू संगठनों ने इस घटना की निंदा करते हुए जीपीएम शहर में मौन जुलूस निकाला। उन्होंने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है।

भाजपा को जनमत पर भरोसा नहीं तो किस मुंह से कांग्रेस के आंदोलन पर टिप्पणी : विनोद

महासमुंद। संसदीय सचिव व कांग्रेस प्रवक्ता विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कांग्रेस के मौन स्त्याग्रह पर छग के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता धरमलाल कौशिक द्वारा जारी बयान का कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने जारी बयान में कहा कि भारत एक लोकत्रांतिक देश है जंहा सरकार चुनने का अधिकार संविधान में जनता के पास है, पर भाजपा के नेता जनता द्वारा दिए गए जनमत को गलत करार देते हुए जोड़-तोड़ की राजनीति कर जनता के जनमत को दरकिनार अपनी सरकार बनाते है। पिछले 9 साल के भीतर भाजपा पार्टी ने देश के कुछ राज्यों कांग्रेस व अन्य पार्टियों को जनता द्वारा दिए गए बहुमत के बाद भी विधायकों की खरीद फरोख्त कर अपनी पार्टी की सरकार बनाई। चंद्राकर ने कहा जिस भाजपा पार्टी और उनके नेताओं को जनता के जनमत पर भरोसा नहीं है उनके मुंह से न्यायालय के फैसले के विरोध में मौन सत्याग्रह पर टिप्पणी करना शोभा नहीं देता है।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कोरबा ने किया वृक्षारोपण

कोरबा। कोरबा शहर में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा कोरबा के द्वारा पुरानी बस्ती क्षेत्र में कोरबा मुस्लिम जमात के पास वृक्षारोपण किया गया।

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी जावेद रब्बानी एवं युवा मोर्चा जिला महामंत्री एवं नगर निगम पार्षद नरेंद्र देवांगन उपस्थित रहे। इन्होने इस अवसर पर फलदार, छायादार पौधारोपण किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री यासीन खान, जिला उपाध्यक्ष सैय्यद रियाज फिरोज, जिला कोषाध्यक्ष हब्बी उला अंसारी, जिला सह कोषाध्यक्ष बाजी रूखसार, जिला मंत्री सन्नी सिंह, जिला मीडिया प्रभारी सैय्यद नसीम, जिला सोशल मीडिया प्रभारी करीम अशरफ जिला सोशल सह मीडिया प्रभारी शाहिना परवीन, अमनदीप सिंह,नंदू गोस्वामी, अनिल कुमार, रजत साहु, चंचल, तारा, एवं समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

आम आदमी पार्टी बदलाव पदयात्रा 22 जुलाई से

कोरबा। आम आदमी पार्टी प्रदेश कमेटी के आह्वान पर कोरबा जिले में 22 जुलाई से बदलाव पदयात्रा की शुरुआत हो रही है स

इस यात्रा का नेतृत्व प्रदेश का प्रभारी नरेश बारिया व कोरबा विधानसभा प्रभारी प्रितपाल शर्मा करेंगे स 22 जुलाई को पाली तानाखार के पसान में व कोरबा विधानसभा में यात्रा का आगाज होगा। कोरबा में टीपी नगर से पुराना बस स्टैंड तक पदयात्रा होगी स इसी तरह से 23 जुलाई को रामपुर विधानसभा क्षेत्र के भैंसमा व 14 जुलाई को कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के बाकी मोगरा ब्लॉक में पदयात्रा निकाली जाएगी। कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों से अपील की जा रही है कि पदयात्रा में अधिक से अधिक शामिल होकर कर कार्यक्रम को सफल बनावे।

किसान सभा ने एसईसीएल के गेवरा मुख्यालय को घेरा

■ अधिकारी-कर्मचारी ऑफिस में बने बंधक

कोरबा। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में रोजगार, पुनर्वास, जमीन वापसी से जुड़ी 11 सूत्रीय मांगों पर 40 गांवों के हजारों ग्रामीणों ने सुबह 10 बजे से एसईसीएल के गेवरा मुख्यालय पर डेरा डाल दिया। इन पंक्तियों के लिखे जाने तक रात 10 बजे भी यह घेराव जारी है। भू-विस्थापित रोजगार एकता संघ के सैकड़ों कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। आंदोलनकारियों द्वारा दोनों गेटों को जाम कर देने से आज दिन भर से अधिकारी.कर्मचारी ऑफिस में ही फंसे हुए हैं और उन्हें चाय भी नसीब नहीं हो पा रही है। दो दौर की वार्ता विफल हो जाने के बाद आंदोलनकारियों द्वारा रात में भी घेराव जारी रखने की घोषणा की गई है।

ऐसे में रात में भी उनके निकलने की कोई संभावना नहीं है और अधिकारी-कर्मचारी अपने कार्यालय में ही बंधक हो गए हैं। घेराव कर रहे लोगों में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जिसके कारण प्रशासन आंदोलनकारियों से सख्ती से नहीं निपट पा रहा है।

पिछले 10 दिनों से इस आंदोलन की तैयारियां चल रही थीं। भूमि अधिग्रहण के बदले रोजगार, मुआवजा, पूर्व में अधिग्रहित जमीन की वापसी, प्रभावित गांवों के बेरोजगारों को खदान में काम, शासकीय भूमि पर कब्जाधारियों को रोजगार, बसावट एवं मुआवजा, महिलाओं को स्वरोजगार, पुनर्वास गांव में बसे भू विस्थापितों को काबिज भूमि का पट्टा देने आदि मांगें इस इलाके की बहुत पुरानी मांगें हैं, लेकिन समस्या के समाधान के लिए न राज्य सरकारए न जिला प्रशासन और न ही एसईसीएल कभी आगे आया। यही कारण है कि किसान सभा की पहलकदमी पर नेहरूनगर, विजयनगर, ढूरैना, खुसरूडीह, जुनाडीह, बेलटिकरी, झाबर, कोसमंदा, झींगटपूर, बिंझरा, सुहाभोडी, गंगानगर, मड़वाढोढा, पुरैना, नरईबोध, भैसमाखार, गेवरा, मन गांव, बरपाली, खमहरिया, जरहाजेल, दुल्लापुर, दूरपा, जटराज, सोनपुरी, बरकुटा,भठोरा, भिलाईबाजार, रलिया, बरभांठा, बरेली, रिसदी, खोडरी, सुराकछार बस्ती, कुचैना, दादरपारा, बरमपुर एवं अन्य गांवों के हजारों भूविस्थापित किसान आंदोलन में शामिल हो गए हैं। माकपा जिला सचिव प्रशांत झा, माकपा पार्षद राजकुमारी कंवर, किसान सभा के जवाहर सिंह कंवर, दीपक साहू, नंदलाल कंवर, जय कौशिक, रोजगार एकता संघ के दामोदर श्याम, रेशम, रघु यादव, सुमेन्द्र सिंह ठकराल के साथ प्रभावित गांवों के शिवदयाल कंवर, सुभद्रा कंवर, वीर सिंह, राजेश कंवर, जोहीत राय, संजय, बसंत चौहान, ज्ञान सिंह, भुनेश्वर, देव कुंवर, बहेतरिन बाई, छत बाई, बाबूलाल कंवर आदि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। किसान सभा ने ऐलान किया है कि उनका आंदोलन तभी खत्म होगा, जब एसईसीएल प्रबंधन रोजगार, मुआवजा और बसावट के सवाल पर उनके पक्ष में निर्णायक फैसला करेगा।

वाहन ने मवेशी को मारी ठोकर, नाराज लोगों ने किया चक्काजाम

कोरबा। यहां के परसाभाठा चौराहे पर आज सुबह 5 बजे के आसपास हुई दुर्घटना में एक मवेशी घायल हो गई। घटनाक्रम को लेकर स्थानीय लोगों ने चक्काजाम कर दिया। स्थिति बिगडने पर पुलिस ने संज्ञान लिया। इस सिलसिले में पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया। इसके साथ चक्काजाम समाप्त हो गया।

बताया गया कि आवाजाही के दौरान यह घटना हुई। परसाभाठा में रहने वाले हरिहर नामक व्यक्ति की गाय चौराहे के पास मौजूद थे। उसी दरम्यान एक मालवाहक की चालक ने उसे ठोक दिया। इससे गाय बुरी तरह से घायल हो गई। हादसे की जानकारी होने पर यहां लोगों की भीड़ लग गई। उन्होंने यातायात व्यवस्था पर नाराजगी जताने के साथ चक्काजाम कर दिया। इसके नतीजन कोरबा और रिंग रोड पर वाहनों की लाइन लग गई। आम आवागमन भी इससे बाधित हुआ। पुलिस ने इस पर संज्ञान लेने के साथ अगली कार्रवाई की। बताया गया कि मवेशी के उपचार और अन्य कार्यों के लिए पीड़ित पक्ष को 50 हजार की तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। संबंधित ने इस पर संतोष जताया है। इस कार्रवाई के साथ चक्काजाम खत्म हो गया। इससे पहले भी कई मौके पर परसाभाठा चौराहे की समस्याओं और लगातार मंडरा रहे खतरों को लेकर आसपास के लोगों ने नाराजगी का प्रदर्शन किया है। इन सबके बावजूद इस क्षेत्र की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आवश्यक जतन नहीं किये गए हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ को भेजा दिल्ली अध्यादेश मामला

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र के सेवा अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश पारित किया। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एससी बेंच ने कहा, 5 जजों की बेंच संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाले 2019 के फैसले को चुनौती देने की कार्यवाही के समापन के बाद अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगी। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ.अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि एक संदर्भ का मतलब यह नहीं है कि एक संदर्भ आवश्यक नहीं है क्योंकि इस मुद्दे पर 3-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। सिंघवी ने दलील दी कि अध्यादेश अनुच्छेद 239एए के प्रावधानों के खिलाफ है क्योंकि यह निर्वाचित सरकार की शक्तियों को कमजोर करता है।

नीतीश ने हमेशा अपनी मजबूरी में इस्तेमाल किया : जीतन राम

पटना। एनडीए की बैठक में भाग लेने के बाद दिल्ली से पटना पहुंचे हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि अब राजद और जदयू के बीच खटपट ज्यादा बढ़ गई है। मनमुटाव पहले से था, लेकिन अब लगाता है ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश ने उन्हें कच्चा चारा समझकर मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने सोचा था कि वो जैसा कहेंगे वैसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार की समझदारी एकदम खत्म हो गई है। उन्होंने हमको हमेशा अपनी मजबूरी में इस्तेमाल किया। दरअसल, नीतीश ने बुधवार को कहा था कि अच्छा हुआ था कि हमने मांझी जी को पहले ही पार्टी से हटा दिया था। नहीं तो सभी बैठक की बात वह उधर भाजपा को बताते। इसको लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि वह अब तर्क विहीन हो गए हैं। अगर हम उनके पार्टी में चले गए होते तो इधर-उधर की बात तो और भी ज्यादा हम करते।

प्रियंका चतुर्वेदी ने स्मृति ईरानी से इस्तीफे की मांग की

नईदिल्ली। मणिपुर वीडियो पर स्मृति ईरानी की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह मुद्दा महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री ने तभी उठाया जब वह दबाव में आ गईं। उन्होंने ईरानी को सबसे अक्षम मंत्री बताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। 4 मई का एक वीडियो बुधवार को सामने आया जिसमें युद्धरत समुदायों में से एक की दो महिलाओं को कुछ पुरुषों द्वारा नग्न परेड करते हुए दिखाया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद ईरानी ने इस घटना को निंदनीय और सर्वथा अमानवीय बताया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कभी इस पर बात नहीं की, लेकिन अब जब उन पर दबाव है, तो वह कहती हैं कि उन्होंने सीएम से बात की है। देश के सबसे अक्षम मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। चतुर्वेदी ने कहा कि घटना देश को शर्मसार करती है और उन्होंने इस मुद्दे को संसद में उठाने की भी मांग की।

भाजपा के लिये पूर्वांचल को साधेंगे ओम प्रकाश राजभर

लखनऊ। भाजपा के मिशन 80 का सपना पूरा करने के लिये सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सहारा बनेंगे। वह राजभर वोटों के सहारे बीजेपी के लिये पूरब को साधने का कार्य करेंगे। 2019 में पूर्वांचल की छह सीटों पर बीजेपी का मुंह की खानी पड़ी थी। अब इन सीटों को राजभर वोटों के सहारे जीतने की योजना बनायी गयी है। इसकी शुरुआत आजमगढ़ से होगी। पूर्वांचल के लगभग एक दर्जन जिलों में राजभर बिरादरी लगभग 2.50 फीसदी है। अपनी बिरादरी पर ओम प्रकाश राजभर की अच्छी पकड़ है। यूपी में 2022 विधानसभा का परिणाम देखें तो पता चलता है कि आजमगढ़ और गाजीपुर जिले की सभी सीटें बीजेपी हार गयी थी। इन दोनों ही जिलों में सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जिसे चाहते हैं, अपना वोट ट्रांसफर करा देते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में अंबेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, घोसी, लालगंज, जौनपुर सीट सीटों पर भी बीजेपी अपनी जीत हासिल करना चाहती है।

कांग्रेस संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करती है : भाजपा

नईदिल्ली। मणिपुर से एक वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक बवाल जबरदस्त तरीके से जारी है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल पूरे मामले को लेकर भाजपा पर हमलावर हैं। इन सबके बीच भाजपा की ओर से पलटवार किया गया है। भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि संवेदनशील मुद्दों पर कांग्रेस सिर्फ राजनीति करना जानती है। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन विपक्षी मामला तो उठाते हैं लेकिन चर्चा को तैयार नहीं होते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि हम पूरे आश्वासन और विश्वास के साथ दोहराना चाहेंगे कि मोदी सरकार भारत की महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जो घटना मणिपुर की है वह दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सभी आहत हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है कि संवेदनशील मुद्दों पर आपका दृष्टिकोण क्या है।

संसद में मणिपुर वीडियो मामले को लेकर विपक्ष का हंगामा

दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित

नईदिल्ली। गुरुवार से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। लेकिन पहले ही दिन जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला। हंगामे की वजह से दोनों ही सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हो गई। अब संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11.00 बजे से शुरू होगी। मणिपुर मामले को लेकर दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। एक ओर सरकार का दावा है कि वह मणिपुर को लेकर हर तरह की चर्चा को तैयार है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि हम दोनों सदनों में मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। मणिपुर एक संवेदनशील विषय है। गृह मंत्री विस्तार से चर्चा का जवाब देंगे। स्पीकर को चर्चा की तारीख तय करने दीजिए हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जब अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया और सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है तब क्यों भाग रहे हैं? विपक्ष का प्रस्ताव था और भाजपा का भी प्रस्ताव था कि इसपर चर्चा हो। आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके भी अपना दुख व्यक्त कर दिया है, इन्हें बहाना चाहिए कि सदन की कार्यवाही न चले। हम तो बंगाल पर भी चर्चा चाहेंगे। मणिपुर पर भी चर्चा होनी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 महिलाओं(मणिपुर में) के साथ जिस तरह का व्यवहार और अत्याचार हुआ, उसकी घोर निंदा की है और कड़े शब्दों में कहा है कि कितने भी हो और कोई भी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए... मगर दूर्भाग्य ये है कि विपक्षी दल इसे राजनीति के रूप में देखते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। हमने सदनों में कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार है मगर विपक्ष चर्चा से भागना चाह रहा है।

विपक्ष ने संसद नहीं चलने देने का मन बनाया

राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष संसद को नहीं चलने देने का मन बना चुका है। अपने बयान में पीयूष गोयल ने कहा कि आज सदन की कार्रवाई और व्यापार सलाहकार समिति की बैठक में विपक्ष का रवैया देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि वो मन बनाकर आए थे कि सदन की कार्रवाई नहीं चलने

देंगे। उन्होंने कहा कि शायद उनको परेशानी है कि प.बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा की घटनाएं हुई हैं और छत्तीसगढ़ व राजस्थान में नारी शक्ति का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं ऐसे में सरकार ने जब स्पष्ट कर दिया कि हम मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं उसके बावजूद कांग्रेस और बाकि विपक्षी दल सदन की कार्रवाई को रोका। ये स्पष्ट करता है कि विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती है। हाल ही में निधन हुए सदन के सदस्यों के सम्मान में लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं, मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामे के बीच राज्यसभा दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनायी

विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस (इंडिया)' के घटक दलों ने मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और कहा कि उन्हें सबसे पहले संसद के दोनों सदनों में मणिपुर मामले पर बयान दें और फिर इस मुद्दे पर चर्चा करायें। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले बैठक कर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की। गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद मणिपुर मामले को लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। विपक्ष की बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संसद भवन स्थित कक्ष में हुई। इस बैठक में खरगे के अलावा समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, जनता दल (यूनाइटेड) के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और कई अन्य नेता शामिल हुए।

लोकसभा में चर्चा की मांग

बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ''26 पार्टियों वाले 'इंडिया' की मांग बिल्कुल स्पष्ट है। प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों में 3 मई, 2023 के बाद से मणिपुर में हुए भयावह और दुखद घटनाक्रम पर बयान देना चाहिए और फिर इसके बाद चर्चा होनी चाहि।। यह कार्यसूची में पहले क्रम पर होना चाहिए।'' उधर, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, मणिकम टैगोर और कुछ अन्य विपक्षी सांसदों ने मणिपुर के मामले पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को कार्यस्थगन के नोटिस दिये। लोकसभा सदस्य तिवारी ने सदन में चर्चा की मांग करते हुए कहा था कि सरकार को मणिपुर की स्थिति के बारे में जानकारी देने के साथ ही यह भी बताना चाहिए कि शांति बहाली के लिए क्या उपाय किये गए।

पीएम मोदी से बयान देने की मांग

टैगोर ने नोटिस में कहा कि मणिपुर में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के विषय पर प्राथमिकता के आधार पर चर्चा होनी चाहिए तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की स्थिति के बारे में सदन में स्पष्टीकरण देना चाहिए। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य सैयद नासिर हुसैन ने नियम 267 के तहत दिए नोटिस में शून्यकाल, प्रश्नकाल और अन्य विधायी कार्य स्थगित करके चर्चा की मांग की। शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी नियम 267 के तहत नोटिस देकर उच्च सदन में मणिपुर के विषय पर चर्चा का आग्रह किया। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने मणिपुर के हालात पर चर्चा कराने पर सरकार की सहमति जतायी। किंतु उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष खरगे और तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने इस बात पर बल दिया कि इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में बयान देना चाहिए और उसके बाद कार्यस्थगन प्रस्ताव के नियम के तहत चर्चा करायी जाए।

मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना पर भड़के चीफ जस्टिस

अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे : सुको

नई दिल्ली। मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न कर घुमाने के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ वह पूरा तरह अस्वीकार्य है। सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांप्रदायिक टकराव के क्षेत्र में महिलाओं को किसी चीज की तरह इस्तेमाल करना संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह काफी परेशान करने वाला है। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि हम सरकार को थोड़ा समय दे रहे हैं। अगर आगे जमीन पर कुछ नहीं होता है तो हम खुद कार्रवाई करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार को निर्देश दिया कि इस घटना के जिम्मेदारों के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो, उसके बारे में कोर्ट को

पूरी जानकारी दी जाए। मीडिया में जो भी इस घटना के बारे में दिखाया गया और इस हिंसा के बीच महिलाओं का इस्तेमाल संवैधानिक लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बारे में सभी कदमों की जानकारी दे। सीजेआई ने इस मामले की सुनवाई अगले शुक्रवार तक टाल दी।

पुलिस ने बताया कि अज्ञात हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ थौबल जिले के नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन में अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा : पीएम मोदी

मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल

हो रहा है बताया जा रहा है कि यह वीडियो 3 या 4 मई का है। वहीं, अब महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के वीडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने गुरुवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले कहा कि मणिपुर की घटना देश के लिए शर्मनाक, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा है। माताओं और बहनों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि गुनाहगारों को बक्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आगे कहा, मेरा दिल दर्द और गुस्से से भर गया है। मणिपुर से जो घटना हमारे सामने आई है वह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है. मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्यों में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करें-खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए और सख्त से सख्त कदम उठाएं। राजस्थान की कोई घटना हो या छत्तीसगढ़ की, मणिपुर की या देश के किसी भी कोने की- राजनीति से ऊपर उठें।

खेल
प्रमुख समाचार

भारतीय हॉकी टीम चार देशों के टूर्नामेंट के लिए स्पेन रवाना

नईदिल्ली। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में 24 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम चार देशों के टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए स्पेन रवाना हो गई। स्पेन हॉकी महासंघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर टेरासा में 25 से 30 जुलाई तक चार देशों का टूर्नामेंट खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में मेजबान स्पेन और भारत के अलावा इंग्लैंड और नीदरलैंड की टीमें भी भाग लेंगी।

भारतीय टीम 25 जुलाई को स्पेन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी और फिर 26 जुलाई को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। भारत राउंड रॉबिन चरण के अपने अंतिम मैच में 28 जुलाई को इंग्लैंड से भिड़ेगा। टूर्नामेंट का फाइनल 30 जुलाई को खेला जाएगा। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद एशियाई खेलों की तैयारियों को देखते हुए भारत के लिए यह टूर्नामेंट काफी महत्वपूर्ण है।

भारतीय टीम के रवाना होने से पहले कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा, चार देशों का दौरा हमारी टीम के लिए दुनिया के शीर्ष देशों के खिलाफ खुद को परखने का मौका है। स्पेन, नीदरलैंड और इंग्लैंड पिछले साल अच्छी फॉर्म में रहे हैं और हम दौरे पर अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम- गोलकीपर: श्रीजेश परट्टू रवीन्द्रन और कृष्ण बहादुर पाठक। डिफेंडर: जरमनप्रीत सिंह, नीलम संजीव ज़ेस, मनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), वरुण कुमार और संजय। मिडफील्डर: हार्दिक सिंह (उप-कप्तान), विवेक सागर प्रसाद, सुमित, नीलकंठ शर्मा, शमशेर सिंह, राजकुमार पाल। फॉरवर्ड: ललित कुमार उपाध्याय, मंदीप सिंह, गुरजंत सिंह, सुखजीत सिंह, अभिषेक, पवन, दिलप्रीत सिंह, सिमरनजीत सिंह और कार्थी सेल्वम।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 474 अंक चढ़ा, निफ्टी 20000 के करीब पहुंचा

नई दिल्ली। वीकली एक्सपायरी के दिन भी भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड बढ़त जारी रही। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी गुरुवार को इंट्रा डे में नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। गुरुवार को सेंसेक्स 474.46 (0.71%) अंकों की बढ़त के साथ 67,571.90 के लेवल पर बंद हुआ वहीं दूसरी ओर निफ्टी 146.00 (0.74%) अंक चढ़कर 19,979.15 अंक के स्तर पर बंद हुआ। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन निफ्टी पहली बार 20,000 काफी करीब तक पहुंचा। निफ्टी इंडेक्ट इंट्राडे में 19,991 के लेवल तक पहुंचने में सफल रहा। सेंसेक्स के शेयरों में आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर दो-दो प्रतिशत से ज्यादा उछले। मारुति, एयरटेल, एसबीआई, सन फार्मा, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक्सिस बैंक के शेयर भी हरे निशान पर बंद हुए। दूसरी ओर, इंफोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचसीएल टेक और बजाज फिनसर्व के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए।

जियो फाइनैंशियल सर्विस 20 अरब डॉलर की कंपनी बनी

नईदिल्ली। भारत के अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी की जियो फाइनैंशियल सर्विस कंपनी गुरुवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग यानी डीमर्ज हो गई है। डीमर्जर से पहले स्टॉक एक्सचेंज ने स्पेशल प्री-ओपेन सेशन भी आयोजित किया था। जियो फाइनैंशियल सर्विस कंपनी का गुरुवार को स्टॉक मार्केट में डीमर्जर होते ही कंपनी का शेयर प्राइस विश्लेषकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा ही उछल गया। छ्व्स्नस् का शेयर प्राइस 261.85 रुपये फिक्स होने के बाद इसकी वैल्यू करीब 20 अरब डॉलर आंकी गई है। रॉयटर्स ने यह जानकारी दी। डीमर्जर, जिसे पिछले अक्टूबर में घोषित किया गया था, को तेल-से-खुदरा समूह रिलायंस के आकर्षक वित्तीय सेवा क्षेत्र में विस्तार के तरीके के रूप में देखा जाता है, खासकर जब से उसके पास पहले से ही एक गैर-बैंक वित्तीय कंपनी का लाइसेंस है।

इन्फ्रा बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रु. जुटाएगा एसबीआई!

नईदिल्ली। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जुलाई महीने के अंत तक 10 हजार करोड़ रुपये तक का फंड जुटाने की योजना बना रहा है। एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स की बिक्री के जरिए ये फंड जुटा सकता है। खबर के मुताबिक बैंक 5,000 करोड़ रुपये के बेस साइज एवं 5,000 करोड़ रुपये के ग्रीन शू ऑप्शन के साथ 15 साल के इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जारी कर सकता है। इसी साल जनवरी महीने में बैंक ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स जारी किए थे, इन बॉन्ड्स की 15-साल की मेच्योरिटी थी। बता तें, ये पहली बार थी जब किसी भी भारतीय बैंक ने 15 साल की मेच्योरिटी अवधि के इस तरह के बॉन्ड जारी किए थे। बैंक का अनुमान है कि 15 साल के इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्रैकेट में अधिक (बॉन्ड्स) इश्यू किए जाने से लंबी अवधि के मेच्योरिटी सेग्मेंट में अधिक फंड जुटाने को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग लिए बेहतर कीमत तय करने में मदद मिलेगी।

हैवेल्स ने पहली तिमाही में कमाए 287 करोड़ रुपये

नईदिल्ली। बिजली के सामान और अप्लायंस बनाने वाली कंपनी हैवेल्स इंडिया ने गुरुवार को कहा कि 30 जून, 2023 को समाप्त पहली तिमाही में उसका समेकित शुद्ध लाभ 18 प्रतिशत बढ़कर 287 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष अप्रैल-जून में 243 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। हैवेल्स इंडिया ने एक्सचेंजों को फाइलिंग में बताया कि जून तिमाही में कुल आय बढ़कर 4,899 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले की अवधि में 4,292 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने कहा कि पहली तिमाही में उपभोक्ता मांग सुस्त रही, हालांकि हाल ही में इसमें तेजी आई है।

कारोबारी बढ़त की संभावनाओं के बीच सतत विकास की राह पर अर्थ-तंत्र

जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), फ्रांस और अमेरिका की यात्राओं के दौरान इन देशों के साथ जो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, उनसे भारत में कारोबार के तेजी से बढ़ने तथा टिकाऊ आर्थिक विकास व निवेश साख बढ़ने की अभूतपूर्व संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी) की डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा संबंधी रिपोर्ट-2023, इनवेस्को ग्लोबल की सोवरेन वेल्थ फंड निवेश रिपोर्ट-2023 और निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स की भारत की आर्थिक संभावना रिपोर्ट-2023 में भी भारत की बढ़ती हुई आर्थिक, वित्तीय और निवेश अहमियत को रेखांकित किया गया है।

यूएनईएससीएपी की रिपोर्ट में भारत 140 देशों को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे आगे पहुंच गया है। इनवेस्को ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक, सोवरेन वेल्थ फंड के निवेश को लेकर दुनिया के 142 मुख्य निवेश अधिकारियों ने भारत को पहली पसंद बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की कारोबारी व राजनीतिक स्थिरता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो उसका मजबूत पक्ष है। भारत में विदेशी निवेश बढ़ रहे हैं, राजकोषीय घाटा कम हो रहा है और राजस्व संग्रह में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा, भारत की आबादी, नियामक पहल और सोवरेन निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल से भी भारत के निवेश के लिए पहली पसंद बनने में मदद मिली है। विकासशील देशों में निवेश के लिए अब चीन नहीं, बल्कि भारत निवेशकों की पहली पसंद बन गया है।

निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के लिए नवाचार और

बढ़ती श्रमिक उत्पादकता महत्वपूर्ण होने जा रही है। पूंजी निवेश भी भविष्य में विकास का एक महत्वपूर्ण चालक होगा। बढ़ती आय और गहरे वित्तीय क्षेत्र के विकास के साथ अनुकूल जनसांख्यिकी के कारण भारत की बचत दर बढ़ने की उम्मीद है।

निस्संदेह वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत तेजी से टिकाऊ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट-2023 में कहा गया है कि देश में बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है। बैंक और कंपनियों के बही-खाते मजबूत हुए हैं। मार्च, 2023 में देश के बैंकों के फंसे हुए कर्ज का अनुपात घटकर 3.9 फीसदी और शुद्ध एनपीए अनुपात एक फीसदी रह गया है, जो विगत 10 साल का निम्नतम स्तर है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मुनाफा निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में तेजी से बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष में देश की विकास दर अनुमानों से अधिक 7.2 फीसदी रही है। दुनिया भर के वित्तीय संगठनों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर के छह से 6.5 फीसदी रहने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माता है और तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। भारत का फार्मा उद्योग उत्पादित मात्रा के आधार पर दुनिया में तीसरे क्रम पर है। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई शक्ति प्राप्त कर रहा है। देश में उद्योग-कारोबार को आसान बनाने के लिए विगत नौ वर्षों में करीब 1,500 पुराने कानूनों और 40 हजार अनावश्यक अनुपालन को समाप्त किया गया है। घरेलू मांग भारतीय अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत है। भारत में निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलता है। देश में प्रतिभाशाली नई पीढ़ी की कौशल दक्षता, आउटसोर्सिंग और बढ़ते हुए मध्यवर्ग की क्रयशक्ति के कारण भारत की आर्थिक अहमियत तेजी से बढ़ी है। भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए टिकाऊ आर्थिक वृद्धि एवं निवेश साख को और मजबूत बनाना होगा, देश में लागू नई लॉजिस्टिक नीति व गति शक्ति योजना के कारगर अमल पर अधिक ध्यान देना होगा, सभी उत्पादों के कारोबार के लिए सिंगल विंडो मंजूरी, इन्फ्रास्ट्रक्चर और कुशल श्रमिकों की आपूर्ति के साथ-साथ विभिन्न आर्थिक और वित्तीय सुधारों की डगर पर आगे बढ़ना होगा तथा श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ानी होगी।

समाचार पचीसा
रायपुर, शुक्रवार 21 जुलाई 2023

एनडीए के सामने कैसे जीतेगा इंडिया?

उमेश चतुर्वेदी

राजनीतिक इतिहास में गठबंधन करने और उन्हें अनूठे नाम देने का चलन कांग्रेस विरोधी धड़ों का रहा है। लेकिन अब अनूठे नाम रखना उस कांग्रेस की अगुआई वाले गठबंधन की मजबूरी हो गया है, जिसके खिलाफ अतीत में गठबंधन बनते रहे हैं। बेंगलुरू की बैठक में कांग्रेस की अगुआई वाले गठबंधन को अब इंडिया नाम से जाना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इंडिया एनडीए को केंद्र की सत्ता से उखाड़ने में कामयाब होगा? इन बुनियादी मुद्दों पर चर्चा से पहले हमें इस गठबंधन के नए नाम के अर्थ पर ध्यान देना चाहिए। इंडिया के आई से इंडियन, एन से नेशनल, डी से डेमोक्रेटिक, आई से इन्क्लुसिव और ए से अलायंस यानी इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इन्क्लुसिव अलाएंस। इसको हिन्दी में भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समावेशी गठबंधन कह सकते हैं। इस नए नाम से साफ है कि इस गठबंधन ने देश को यह संदेश देने की कोशिश की है कि यह समन्वित और समावेशी गठबंधन है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एनडीए में जो 36 दल शामिल हुए हैं, उनका नजरिया समावेशी नहीं है? चूंकि नए गठबंधन के नाम की चर्चा चली है तो अतीत के कांग्रेस विरोधी गठबंधनों के नामों पर भी देखना चाहिए। 1989 में कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी दलों ने जो मोर्चा बनाया था, उसका नाम था राष्ट्रीय मोर्चा। इसी तरह विपक्षी दलों ने 1996 में संयुक्त मोर्चा नाम से गठबंधन बनाया। उसके बरक्स उन्हीं दिनों भारतीय जनता पार्टी की अगुआई में एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना। 2004 में पहली बार कांग्रेस की अगुआई में गठबंधन बना, जिसे नाम यूपीए यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन नाम दिया गया। इस संदर्भ में देखें तो कांग्रेस की अगुआई में राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया दूसरा गठबंधन है। वैसे केरल में अरसे से कांग्रेस संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन चला रही है। एक और तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अतीत में कांग्रेस विरोधी गठबंधनों को सफलता मिली है। उसी तरह साल 2004 में सत्ता विरोधी गठबंधन यूपीए को जीत मिली। कुछ इसी अंदाज में मोदी विरोधियों की बेंगलुरू बैठक के बाद बांछे खिल गई हैं। उन्हें लगने लगा है कि नीतीश कुमार की मेहनत कामयाब होने जा रही है। साल 2024 के चुनाव में उन्हें मोदी की हार तय लग रही है। लेकिन अतीत के गठबंधन और उस दौर के माहौल की ओर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले साल 1977 के चुनाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उस वक्त करीब तीन साल से जयप्रकाश नारायण की अगुआई में देश में बदहाली, इंदिरा की तानाशाही और बढ़ती महंगाई के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। एक तरह से माहौल पहले से बना था और बाद में कांग्रेस विरोधी दल एक हुए और उन्होंने जनता पार्टी बनाई। तब इंदिरा विरोधी माहौल बन गया था। बस विपक्षी दलों ने इस माहौल को भांपा, साथ आए और कांग्रेस को पटखनी दी। कुछ इसी तरह साल 1989 में भी माहौल बना था। साल 1987 से बोफोर्स तोप सौदे में कांग्रेस को 64 करोड़ की दलाली मिलने को लेकर कांग्रेस विरोधी माहौल बनने लगा था। तब देवीलाल ने हरियाणा में परिवर्तन रथ चला रखा था तो आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव ने अभियान शुरू कर रखा था। कांग्रेस का साथ छोड़कर विश्वनाथ प्रताप सिंह भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार की माला जप रहे थे और फिर माहौल बदलने लगा। 1987 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से राजीव गांधी की नहीं बन रही थी। असम और पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था।

'इंडिया' बनाम 'भारत' के नए खतरे

अजय बोकिल

देश में 18 वीं लोकसभा के लिए 2019 में होने वाले चुनावी महाभारत में अब जिस तरह की राजनीतिक लामबंदी हो रही है, उससे इसके लक्ष्य से भटक जाने की संभावना ज्यादा है। यह भटकाव जन मुद्दों से 'इंडिया' बनाम 'भारत' का होगा। तमाम वादों, विवादों और विसंगतियों के बावजूद इस चुनाव का केन्द्रीय लक्ष्य येन-केन-प्रकारेण मोदी सरकार को हटाना अथवा मोदी सरकार को हर कीमत पर तीसरी बार सत्ता में लाना है। इसमें विपक्षी पार्टियों का अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने का संघर्ष भी शामिल है, जिसे संविधान और लोकतंत्र बचाने की शक्ल में पेश करने की कोशिश हो रही है।

दस साल से भारत हिंदुत्व और आर्थिक विकास के डबल डेकर कॉरिडोर पर चलने की कोशिश कर रहा है, उसे यूं ही आगे बढ़ना चाहिए। खास बात यह है कि यह राजनीतिक गोलबंदी वैचारिक आग्रहों और प्रतिबद्धताओं को दरकिनार कर हो रही है, जिसमें सत्ता स्वार्थ सर्वोपरि है। चूंकि लोकतंत्र में सत्ता की लड़ाइयां चुनाव के माध्यम से होती हैं, इसीलिए दो प्रमुख खेमे नए राजनीतिक मेकअप के साथ सामने दिख रहे हैं। बेंगलुरू में हुई 26 विपक्षी दलों की बैठक में दिलचस्प डेवलपमेंट विपक्षी महाजुटान के नए नामकरण का हुआ है। इस खेमे ने अपना पुराना नाम यूपीए छोड़कर नया नाम 'इंडिया' धारण किया है, जोकि अंग्रेजी के 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' का संक्षिप्तीकरण है। नाम को देखकर लगता है कि पहले संक्षिप्तीकरण सोचा गया, उसके बाद शब्द डाले गए। क्योंकि इसका उस हिंदी में जो देश के 80 करोड़ लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है, में अनुवाद बेहद जटिल यानी 'भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन' (भाराविसग) होगा। कहा जा रहा है कि नए नामकरण के पीछे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेरणा रही है। सोच यह है कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने भाषणों में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तो प्रहार कर सकते हैं, लेकिन 'इंडिया' का विरोध किस मुंह से करेंगे? उन्होंने ऐसा किया तो क्या यह भारत और प्रकारांतर से भारत की जनता का विरोध नहीं होगा? इस नामांतरण से यह भी संदेश भी निहित है कि यूपीए में शामिल लों ने मान लिया है कि पुराना नाम अब राजनीतिक अपशकुन का शिकार हो गया है।

हालांकि, 'नामांतरण' से 'भाग्यांतरण' की उम्मीद पालने का टोटका पुराना है। वह हमेशा कामयाब हो, जरूरी नहीं है। लेकिन असली सवाल भी इसी 'नामांतरण' में छिपा है। नए नाम के जरिए जिस 'इंडिया' को बचाने की बात की जा रही है, क्या वही 'भारत' भी है? क्या आज 'इंडिया' से ज्यादा जरूरत 'भारत' बचाने की नहीं है? इसी मुद्दे पर बीजेपी ने पलटवार शुरू कर दिया है।

असम के मुख्यमंत्री हिंमत बिस्वा सरमा ने कटाक्ष किया कि अंग्रेजों ने देश का नाम 'इंडिया' रखा था। हमें औपनिवेशिक विरासतों से राष्ट्र को मुक्त करने के लिए लड़ना चाहिए। वैसे आजादी के बाद ही से ही यह बात कही जाती रही है कि भारत में दो देश बसते हैं, पहला है- 'इंडिया', जो समाज के प्रभुत्वशाली, आर्थिक रूप से सम्पन्न, अंग्रेजीदां और ऐसी ही महत्वाकांक्षा रखने वालों का देश है और दूसरा- 'भारत' है, जो गरीबों, किसानों और देसी भाषा बोलने समझने तथा एक न्यूनतम सम्मान जनक जिंदगी जीने चाह रखने वालों का देश है। तो क्या भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक द्वंद्व का मूल यही है? जहां तक 'यूपीए' के 'इंडिया' में बदलाव की बात है यह केवल शाब्दिक परिवर्तन नहीं है। इसमें कुछ हद तक भारत की आत्मा को बचाने के हर संभव प्रयास और राजनीतिक मतांतरण को भी मान्य करने का आग्रह निहित है। राजनीतिक मतातंरण इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने पहले तो सॉफ्ट हिंदुत्व को स्वीकार किया। अब वह सॉफ्ट नेशनलिज्म (नरम राष्ट्रवाद) को गले लगाने भी तैयार है। मूव यही है कि भाजपा को उसी की पिच पर बोल्ड किया जाए। इसीलिए वैचारिक और स्थानीय आग्रहों के मामले में परस्पर विरोधी नेता और दल भी एक पंगत में साथ खाना खाने के लिए तैयार हैं। बशर्ते मोदी और भाजपा का आक्रामक राष्ट्रवाद पराजित हो। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ एनडीए (नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस) नई चाल के साथ पुरानी लीक पर ही चल रहा है। एनडीए के 25 साल के इतिहास में फर्क इतना आया है कि बावजूद इसके कुछ पुराने साथियों के खेमा बदलने के उसका जनाधार बढ़ा ही है। भले वह सीटों में न बदला हो। कुछ पुराने साथियों द्वारा एनडीए छोड़ने के बाद अब कुछ नए और मामूली राजनीतिक हैसियत रखने वाले स्थानीय रिसालदार एनडीए की छतरी में अपना सियासी भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं।

बेंगलुरू की विपक्षी महाजुटान को यकीन है कि वर्तमान हालात में 'इंडिया' नाम आम मतदाता में नई फुरफुरी और चेतना पैदा करेगा, जो चुनावी जीत का समीकरण बदल सकता है। लेकिन यह लक्ष्य कठिन इसलिए है कि भाजपानीत 'एनडीए' और 'इंडिया' के बीच वोट बैंक की बड़ी खाई है। आंकड़ों को देखें तो 2004 के बाद से 'एनडीए' का वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है। यह 2004 में 22.18 प्रतिशत था, जो 2019 में बढ़कर 37.36 प्रतिशत हो गया। जबकि यूपीए का वोट प्रतिशत 2004 व 2009 में तो बढ़ा, लेकिन 2014 व 2019 के चुनाव में 19 फीसदी के आसपास स्थिर है।

इसका सीधा अर्थ यह है कि जब तक 'इंडिया' अपना वोट बैंक 37 फीसदी के पार नहीं ले जाता, लाल किले पर उसका कब्जा सपना ही होगा। वोट बैंक दोगुना करना आसान काम नहीं है। यह तभी संभव है, जब विपक्ष के पास दमदार चेहरा, ठोस कार्यक्रम और देश को आगे ले जाने का स्पष्ट रोड मैप हो। संविधान और लोकतंत्र को बचाने जैसे जुमले सैद्धांतिक ज्यादा हैं। यह राजनीतिक हितों से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। खासकर तब कि जब इस देश में अब 'रेवड़ी कल्चर' को राजनीतिक मान्यता मिल चुकी हो। अलबत्ता 2024 के चुनाव में 'इंडिया' का वोट दो-चार प्रतिशत बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ राज्यों में मजबूत जनाधार वाले दल उसमें शामिल हो गए हैं। लेकिन यहां भी पेंच यह है कि जनाधार वाले शिवसेना, राकांपा व अकाली दल में फूट पड़ने से उनका खुद को वोट बैंक दरक रहा है। ऐसे में 'इंडिया' को उसका सीमित लाभ ही मिल सकेगा। दूसरी तरफ एनडीए वोट बैंक की इस कमी को उन छोटे दलों को अपने खेमे में लाकर पूरी कर सकता है, जिनका वोट दो चार प्रतिशत है और जो ज्यादा आंख दिखाने की स्थिति में नहीं हैं। यानी दिल्ली की सत्ता में बदलाव तभी संभव है, जब जनता मोदी और भाजपा को हर कीमत पर हराने पर उतारू हो, जिसकी कोई संभावना नजर नहीं आती। तो क्या 'इंडिया' का जुमला 'भारत' पर भारी पड़ेगा या नहीं? अभी संभावनाएं धुंधली ही हैं।

इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस मोर्चे का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस का पसोपेश में होना भी है। खुद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के अनिच्छुक बताए जाते हैं। ऐसे में सवाल नेतृत्व पर अटकेगा। 26 दलों के बीच सम्बन्धित राज्यों में लोकसभा सीटों का बंटवारा भी टेढ़ी खीर है, जिसमें अभी कई पेंच आने हैं। लोकसभा चुनाव को वन टू वन मुकाबले में तब्दील करने के लिए सभी दलों को पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर राजनीतिक त्याग करना होगा। जो व्यवहार में कैसा होगा, यह देखने की बात है।

यहां दो तर्क 1977 और 2004 के लोकसभा चुनाव के दिए जाते हैं। पहले मामले में जनता पार्टी द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी नीत कांग्रेस को पराजित करना और दूसरे मामले में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता के बावजूद एनडीए का नवोदित यूपीए के हाथों पराजित होने का है। जनता पार्टी का प्रयोग तत्कालीन भारतीय जनसंघ सहित 6 पार्टियों के एक पार्टी में विलीनीकरण के तौर पर हुआ था। लेकिन उस वक्त भी गैर कांग्रेसी 32 पार्टियां उसमें शामिल नहीं थी। जनता पार्टी को उस चुनाव में 41.32 फीसदी वोट मिले थे, जो अब किसी भी विपक्षी पार्टी को मिले सर्वाधिक वोट हैं। लेकिन जनता पार्टी भी मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में ही जीती थी और दक्षिण में कांग्रेस ने अपना किला बचाया था। जनता पार्टी के पास तब जयप्रकाश नारायण और कुछ पुराने कांग्रेस नेताओं का नेतृत्व था। लेकिन जपा की जीत का असली कारण श्रीमती गांधी द्वारा देश में लागू आपातकाल को लेकर जनता में फैला रोष था। चूंकि यह जपा भी दलो का बेमेल वैचारिक गठजोड़ थी, इसलिए यह प्रयोग ढाई साल बाद ही असफल हो गया। 2004 में भाजपानीत एनडीए अटलजी जैसा दमदार चेहरा होने के बाद भी इसलिए हारा, क्योंकि तब उन्होंने उदारवादी राजनीति की दरी तले हिंदुत्ववादी विचार को दबा दिया था। भाजपा और एनडीए के बढ़ते जनाधार के पीछे असली वजह राम मंदिर को लेकर बहुसंख्यक हिंदू वोटरों की विस्तारित होती गोलबंदी रही है, लेकिन अटल सरकार ने राम मंदिर जैसे कोर इश्यु को भी ठंडे बस्ते में डाला हुआ था। साथ ही 'फील गुड' फैक्टर भी एनडीए को ले डूबा।

बारीकी से देखें तो 2019 के चुनाव में मोदीजी के खाते में नोटबंदी जैसे नकारात्मक मुद्दे ज्यादा थे। लेकिन एयर स्ट्राइक जैसे कदमों ने उनकी निर्णायक छवि को चमकाया। आज मोदी पर सर्वसत्तावाद, तानाशाही रवैये और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने जैसे विपक्षी आरोपों के बाद भी उनके खाते में राम मंदिर, कश्मीर से धारा 370 हटाने, एनसीए लागू करने और जल्द ही यूसीसी लाने जैसे काम होंगे। नरेन्द्र मोदी की सबसे बड़ी सफलता यह है कि उन्होंने भाजपा से हटकर अपना एक प्रतिबद्ध वोट बैंक भी खड़ा कर लिया है, अगर हम इसे 'भारत' मानें तो उससे पार पाना 'इंडिया' के लिए बेहद कठिन है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् (भाग-11)

गतांक से आगे...

जल वाले भाग में श्रीनारायण का ध्यान करे, अग्नि वाले स्थान में प्रद्युम्न का चिन्तन करे, वायु क्षेत्र में संकर्षण का एवं आकाश वाले अंश में परमात्मा वासुदेव का चिन्तन सतत करता रहे। जो योगी साधक इस अभ्यास को नियम सहित निरन्तर करता रहता है, वह परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर लेता है। सर्वप्रथम योगासन पर आरूढ़ होकर हृदय प्रदेश में हृदय की विशेष आकृति का चिन्तन करते हुए स्थित होकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करे। जिह्वा को तालु से स्पर्श करे, दाँतों का दाँतों से संस्पर्श करते हुए शरीर को ऊँचा करके समाहित होकर बैठे। विशुद्ध आत्मबुद्धि द्वारा इन्द्रियों का संयम करता हुआ परब्रह्म परमात्मा वासुदेव का ध्यान करे।

योगी को कैवल्य की प्राप्ति अपने अन्तःकरण में संव्याप्त परमात्मतत्त्व के स्वरूप का निरन्तर चिन्तन करने से होती हैं। इस प्रकार एक प्रहर तक कुम्भक करते हुए जो योगी परब्रह्ममय वासुदेव का ध्यान करता है, उसके सात जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नाभिकेन्द्र से लेकर के हृदयप्रदेश तक जाग्रत् अवस्था का क्षेत्र है, स्वप्रावस्था कण्ठ में, सुषुप्तावस्था तालु के मध्य में एवं तुर्यावस्था भृकुटियों के मध्य में प्रतिष्ठित है तुरीयावस्था का क्षेत्र ब्रह्मरन्ध्र में परब्रह्म की ओर लक्ष्य करके स्थित रहता है। जाग्रत अवस्था से शुरू होकर ब्रह्मरन्ध्र तक तुरीयावस्था का आत्मतत्त्व प्रतिष्ठित रहता है, उसके अन्त में वह विष्णु के नाम से कहा गया है। तत्पश्चात् योगी साधक को अत्यन्त निर्मल स्वच्छ आकाश में कमल रूपी हृदय में आसीन कोटि-कोटि सूर्य के सदृश प्रकाश से युक्त नित्य विश्वरूप विष्णु का निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिए। उन अनेक आकार-प्रकार वाले, अनेक मुखों से युक्त, अनेक भुजाओं से संयुक्त, अनेकों आयुधों से मण्डित, विभिन्न वर्णों को धारण किये हुए, देवस्वरूप, शान्त, उग्र, अनेक आयुधों को धारण किये हुए, अनेक नेत्रों से सम्पन्न, कोटि-कोटि सूर्यो की प्रभा से सम्पन्न विश्वस्वरूप भगवान् श्रीविष्णु का चिन्तन-मनन करने से योगी की समस्त मनोवृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। हृदय कमल के मध्य स्थल में प्रतिष्ठित चैतन्यमय, ज्योतिस्वरूप, अव्यय, कदम्ब के सदृश गोलाकार, तुर्यातीत, परात्पर, अन्तरहित, आनन्दमय, चिन्मय, प्रकाशमान, विभु निवांत स्थल में स्थित दीपक की भाँति अकृत्रिम मणि की कान्ति से युक्त परब्रह्म का ध्यान करने से मुक्ति योगी के करतलगत स्थित रहती है।

क्रमशः ..

खत लिखकर देता हूँ शहीदों को श्रद्धांजलि

जितेन्द्र सिंह

मैं भी सेना में जाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं सका। जब दो दशक पहले कारगिल युद्ध हो रहा था, तो मेरे पिता मुझे शहीदों के बारे में बताया करते थे। उसी वक्त मैंने सोचा कि अब मैं शहीदों के परिवार को खत लिखूँगा। मेरे पूर्वज द्वितीय विश्वयुद्ध के वक्त से ही भारतीय सेना का हिस्सा रहे हैं। मेरे पिता भी महार रेजिमेंट का हिस्सा रहे हैं। मैं मूलतः राजस्थान का रहने वाला हूँ, पर फिलहाल गुजरात के सूरत में गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ।

मेरा मानना है कि सेना में जाकर देश की सेवा करना एक कठिन काम है। इस कारण देश के हर नागरिक का दायित्व है कि वह उन शहीदों को हमेशा याद रखें, जिन्होंने हमारी और देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी। मैं शहीदों के परिवार को इसलिए चिट्ठी लिखता हूँ, ताकि उन्हें एहसास हो कि उनके पिता, पति, भाई, बेटे आदि की शहादत को आज भी कोई याद करता है।

खत लिखने के अलावा मैं अब तक 40-50 सैनिकों के परिवार वालों से भी मिला हूँ। शहीदों के परिवार से मैं जब भी मिलता हूँ, तो उनके घरों के आँगन की मिट्टी अपने साथ लेकर आता हूँ। उद्देश्य यही है कि मैं इसी मिट्टी का प्रयोग करके एक विशेष शहीद स्मारक बनवाऊँ। शहीदों के घरवाले मुझसे अपने बेटे जैसा ही व्यवहार करते हैं। इस दौरान मैं 95 साल के बुजुर्ग चुन्नी सिंह जैसे लोगों से भी मिला हूँ, जिनके लिए चिट्ठी लिखने के अलावा भी कुछ काम करने को मिलता है। दरअसल चुन्नी सिंह को 65 साल के बाद पेंशन मिली थी, जिसमें मैंने उनकी मदद की थी। ये परिवार मेरे लिखे हुए पत्र बेहद भावुकता से पढ़ते हैं। पत्र पढ़ते हुए उन्हें ऐसा लगता है, जैसे उनका बेटा उनसे बात कर रहा है। इन वीर शहीदों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए मैंने दिल्ली स्थित सेना मुख्यालय में शहीदों के पते जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पता देने से इनकार कर दिया।

लेकिन मैं निराश नहीं हुआ और अखबारों और मीडिया के दूसरे माध्यमों से जानकारी जुटाने लगा। मैं अखबारों में सैनिकों की वीरता की कहानियाँ ढूँढ़ता रहता हूँ। कई ऐसी कहानियाँ होती है, जो दिल को छू जाती हैं। मैं शहीदों के परिवारों को बस इतना बताना चाहता हूँ कि वे अकेले नहीं हैं, उनके बारे में सोचने वाला एक इंसान और भी है। करीब बीस वर्षों से लगातार चिट्ठिया लिखने के कारण मेरे पास कई क्विंटल स्टेशनरी इकट्ठा हो गई है। मेरे पास करीब चालीस हजार शहीदों का लेखा-जोखा है और इनके परिवारों को मैंने हजारों खत लिखे हैं। मैंने अपने छोटे से घर में खत लिखने के लिए एक अलग स्थान नियत कर रखा है।

मेरे लिए यह काम ईश्वर की उपासना सरीखा है और इसका कार्यस्थल मंदिर जैसा पवित्र । इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हर महीने सिर्फ चंद हजार रुपये ही कमा पाता हूँ। घर के खर्चों को न्यूनतम रखते हुए मैंने अपना जुनून जारी रखा है। हालांकि बीस साल पहले की तुलना में आज खत लिखने का काम कई गुना महँगा हो चुका है। शहीदों के प्रति मेरा सम्मान ही है कि मैंने अपने बेटे का नाम शहीद हरदीप सिंह के नाम पर रखा है, जो पंद्रह साल पहले कश्मीर में आंतकियों से जंग लड़ते हुए शहीद हो गए थे।

अमित शाह ने संभाली पार्टी की चुनावी कमान

हरीश गुप्ता

हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हार के बाद यह साफ तौर पर सामने आ रहा है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस साल के अंत में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की कमान अपने हाथ में ले ली है। अमित शाह ने इन पांच राज्यों में पार्टी प्रभारियों के अलावा अपने कुछ वफादार मंत्रियों को राज्य प्रभारी के रूप में तैनात किया है। प्रधानमंत्री हिमाचल में हार से बेहद निराश थे जहां भाजपा के सत्ता बरकरार रखने की अच्छी संभावनाएं थीं। लेकिन कर्नाटक में हार के बाद, अमित शाह इन राज्यों में पार्टी के गुमराह नेताओं से कठोरता से निपट रहे हैं। दूसरे दलों के नेताओं को स्वीकार करने और अलग हुए सहयोगियों को संतुष्ट करने की खुली नीति एक मेगा योजना का हिस्सा है।

अमित शाह एक तरह से राजस्थान में जीत हासिल करने को लेकर बेहद आश्वस्त हैं और मध्य प्रदेश में बहुत मेहनत कर रहे हैं, जहां सभी सर्वेक्षणों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमजोर स्थिति में हैं। लेकिन अमित शाह ने तय किया कि इतनी देर से अब मुख्यमंत्री बदलने से काम नहीं चलेगा और पूरा समर्थन दिया। उधर चौहान ने मतदाताओं को लुभाने के लिए एक के बाद एक मुफ्त चीजें देने के लिए राज्य का खजाना खोल दिया है और प्रधानमंत्री मोदी के राज्यों को दिए गए इस उपदेश को हवा में उड़ा दिया है कि चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की वस्तुएं बांटने के प्रलोभनों में न पड़ें। अमित शाह अभी भी भूपेश बघेल का मुकाबला करने के लिए एक चेहरा ढूंढ़ रहे हैं। तेलंगाना छोड़कर भाजपा को कम से कम राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम में जीत का भरोसा है।

यह एक विचित्र स्थिति है जो राजनीतिक क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखी गई, जहां सत्तारूढ़ और प्रमुख विपक्षी दल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले यथासंभव नए सहयोगियों को जोड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने अगर तीन दर्जन से अधिक पार्टियों के एनडीए में होने का दावा किया है तो कांग्रेस ने भी बेंगलुरु में 26 पार्टियों के बड़े आंकड़े का दावा किया है। अधिक से अधिक सहयोगियों को पाने की भाजपा की बेताबी काफी आश्चर्यजनक है, क्योंकि तथ्य यह है कि एनडीए से जुड़े 24 दलों के पास लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है और सात के पास सिर्फ एक लोकसभा सीट है।

मई 2019 में मोदी की जीत के बाद लगभग चार वर्षों तक भाजपा ने शायद ही एनडीए की कभी बैठक की। लेकिन अचानक उसने रणनीति बदल दी और 2024 में एनडीए की लोकसभा सीटों का आंकड़ा 400 तक पहुंचाने के लिए सभी लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। भाजपा के कदम को भांपते हुए, कांग्रेस नेतृत्व भी अधिक से अधिक सहयोगियों को खुश करने के लिए अपनी सीटों की कीमत पर अथक प्रयास कर रहा है। कांग्रेस ने दिल्ली सेवा अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी की मांग मानकर जहां कड़वी गोली निगल ली है, वहीं वह सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है।

गांधी परिवार ने अपने अहंकार को परे रख दिया है और अपनी लोकसभा सीटों को तीन अंकों तक ले जाने के लिए पार्टी सहयोगियों के आगे झुक रही है ताकि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बनाया जा सके। कांग्रेस के 26 दलों के गठबंधन की पहुंच लोकसभा में बेहतर है क्योंकि 18 दलों के पास कम से कम एक या अधिक लोकसभा सांसद हैं। भाजपा के अतिरिक्त प्रयास करने का एक कारण यह है कि उसके पास 160 कमजोर लोकसभा सीटें हैं। यहां तक कि 224 लोकसभा सीटों में, जहां उसे 50त्न से अधिक वोट मिले और शेष 79 पर अच्छे अंतर के साथ जीत दर्ज की थी, उसे 2024 में इस आंकड़े को बरकरार रखने की चिंता है।

एनडीए में सभी प्रकार के दलों और नेताओं को शामिल करने के लिए भाजपा नेतृत्व द्वारा अपनाई गई खुले दरवाजे की नीति ने कैडर में भारी नाराजगी पैदा की है। भाजपा की मदद करने के लिए दशकों तक कड़ी मेहनत करने वाला आरएसएस कुछ हद तक परेशान है क्योंकि पुराने वफादारों को धीरे-धीरे बाहर किया जा रहा है जबकि दलबदलुओं को बड़े पद दिए जा रहे हैं और उन्हें राज्यों और यहां तक कि केंद्र में भी जगह मिल जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा की अलग तरह की पार्टी होने की छवि को नुकसान पहुंचा है और केवल पीएम मोदी की साफ छवि के कारण ही मतदाता भाजपा को वोट देना जारी रख रहे हैं। बढ़ती अशांति के परिणामस्वरूप कर्नाटक और अन्य जगहों पर विधानसभा चुनावों में हार हुई। यहां तक कि महाराष्ट्र में भी भाजपा को एहसास हुआ कि अकेले शिवसेना को तोड़ने से चुनावी लाभ नहीं मिल सकता है और उसने अजित पवार को भी शामिल करने का फैसला किया। लेकिन चुनौती 152 विधानसभा सीटें जीतने की होगी। भाजपा ने 2024 के चुनावों के लिए तैयारी की है, जबकि उसके दो मजबूत सहयोगी आधी सीटों की मांग कर रहे हैं। भाजपा आलाकमान अब पुराने वफादारों को खुश रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहा है। जुलाई 2021 में कैबिनेट फेरबदल के दौरान, एक दर्जन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जबकि इनमें से अधिकांश नेता 75 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा से काफी नीचे थे।

राहुल गांधी की सोच और शैली में बड़ा बदलाव आया है क्योंकि वे खुद को एक आम आदमी के रूप में अधिक से अधिक प्रदर्शित करना चाहते हैं। उनकी भारत-जोड़ो-यात्रा के बाद यह बदलाव और अधिक दिखाई देने लगा। अयोग्य ठहराए जाने के बाद उन्होंने समय सीमा से पहले ही सरकारी बंगला खाली कर दिया। शुरुआती दौर में वह सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ में शिफ्ट हुए लेकिन निजामुद्दीन में किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर किराए का घर ढूंढ़ते रहे। इससे दो संकेत गए-एक तो यह कि उनके पास दिल्ली में अपना कोई घर नहीं है और दूसरा, उन्होंने जोरबाग या गोल्फ लिंक जैसे प्रमुख इलाके में एक बहुत भव्य घर नहीं चुना। जल्द ही वह हुमायूं का मकबरा पार्क में सुबह की सैर करते और लोगों से मिलते-जुलते पाए जा सकते हैं।

बापू की दिनचर्या

शयन

बापू साधारणतः रात में नौ बजे शयन करते। उनके शयन का यह समय आरंभ से निश्चित-सा था। कोचरब-आश्रम के प्रारंभिक दिनों में बिस्तर पर जाते ही वे नहीं सो पाते। वहाँ उस समय अस्पृश्यता निवारण पर वा से उनकी चर्चा होती। कभी-कभी बहुत रात तक दोनों में बहस होती रहती। एक बार सन् 1932 में यरवदा जेल में दिन में काफी थके रहने के कारण वे आठ बजे के पहले ही सो गए, किंतु लंदन में द्वितीय गोलमेज परिषद् के समय सन् 1931 में अत्यंत व्यस्त रहने के कारण आधी रात से पहले शायद ही कभी सो पाते। वहाँ उनको काम करते-करते रात के दो बज जाते। उन दिनों मुश्किल से कुल मिलाकर चार घंटे से अधिक वे नहीं सो पाते। अंतिम दिनों में भी उन्हें ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे तक जागना पड़ता, इसके बाद वे सो पाते। रात में दो-तीन बार उनकी आँखें खुलतीं, किंतु जल्दी ही फिर नींद आ जाती। प्रति दिन रात्रि में शयन के समय बापू के सिर में गरी या आँवले जैसा सादा तेल लगाया जाता। अत्यंत व्यस्त रहने के कारण बा को उनसे पाँच मिनट बात करने का भी समय नहीं मिल पाता। एक बार बा ने उनसे यह शिकायत की। उन्होंने रात में सोते समय सिर में तेल लगाने के व्याज से बातें करने का उनको वचन दिया और वे यह कार्य करती रहीं । बा को अवकाश न रहने पर उनके आदेश से ही कोई दूसरा यह कार्य कर सकता, किंतु बापू की सेवा सुचारु रूप से हो रही है या नहीं, इसका वे पूरा ख्याल रखतीं। बापू की सेवा के ऐसे अवसर प्यारेलाल जी, कनु भाई और मनु बहन को भी मिले थे। दिल्ली में अंतिम दिनों में मनु बहन यह कार्य करतीं। सन् 1932 में यरवदा में संभवतः महादेव भाई देसाई को यह सौभाग्य मिला। आभा बहन, सुशीला बहन, मीरा बहन, ठाकुर बलवंत सिंह और ब्रजकृष्ण चाँदीवाला जैसे बापू के निकट संपर्कय जन सोते समय उनके चरण दबाया करते। अन्य भाई-बहनों को भी उनकी चरणसेवा के ऐसे अवसर मिल जाते । प्यारेलालजी का कथन अक्षरशः सही है कि यह सब करने में उन्हें अपना नहीं, बल्कि सेवकों की भावनाओं का अधिक ख्याल रहता, यद्यपि उनके शरीर को इन छोटी-मोटी सेवाओं की जरूरत थी। **क्रमशः ...**

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल हरिचंदन नई दिल्ली मे आयोजित इंडियन रेडक्रास की बैठक में शामिल हुए

रायपुर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की अध्यक्षता में गत दिवस राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इंडियन रेडक्रास सोसायटी की वार्षिक सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई जिसमें राज्यों के राज्यपाल और रेडक्रास समिति के पदाधिकारी उपस्थित थें। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में रेडक्रास सोसायटी के पिछले वर्षो के आय व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रेडक्रास समितियों और रेडक्रास स्वंय सेवकों को सम्मानित किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ रेडक्रास सोसायटी के सी. ई. ओ. श्री एम. के. राउत, चेयरमैन श्री अशोक अग्रवाल एवं समिति के सचिव डॉ. रूपल पुरोहित भी उपरिथत थें। बैठक के पश्चात छत्तीसगढ़ रेडक्रास के पदाधिकारियों ने केन्द्रीय स्वास्थ मंत्री श्री मनसुख मांडविया से भेंट कर छत्तीसगढ़ रेडक्रास समिति की जानकारी दी।

23 को प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक

रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में 23 जुलाई को दोपहर 2 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन रायपुर में प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित (प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष, ब्लाक अध्यक्ष एवं मोर्चा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष) की बैठक होगी।

22 को राजीव भवन में जिलाध्यक्षों व मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की उपस्थिति में 22 जुलाई को दोपहर 2 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन रायपुर में समस्त जिला, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एंव मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। अखिल कांग्रेस कमेटी डाटा एनालिटिक्स विभाग के राष्ट्रीय समन्वयक एवं एलडीएम के राष्ट्रीय सह-समन्वयक व छत्तीसगढ़ प्रभारी राहुल बल व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा प्रशिक्षक के रूप में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

राजस्व पटवारी संघ ने 500 मासिक संसाधन भत्ता की घोषणा पर मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री का 500 रूपए मासिक संसाधन भत्ता की घोषणा पर प्रतिनिधिमंडल ने आभार जताते हुए उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने बताया राज्य के सभी पटवारियों में इस फैसले से हर्ष है। केंद्र के समान डीए और गृहभाड़ा वृध्दि सहित कर्मचारी हित में लिए गए सभी फैसले ऐतिहासिक हैं। उल्लेखनीय है कि अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा प्रदेश के सभी पटवारियों को 500 रूपए मासिक संसाधन भत्ता सहित कर्मचारी हित में कई घोषणाएं की गयी हैं। इस अवसर पर राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ से श्री भागवत कश्यप, श्री ज्योतिष सर्वे, श्री नीरज सिंह, श्री कमलेश तिवारी, श्री अश्वनी वर्मा, श्री संतोष त्रिपाठी, श्री मुरली वर्मा, श्री सतीश चन्द्राकर, श्री सुदर्शन पनिका, श्री रविकांत सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

छात्रावास अधीक्षक-अधीक्षिका भर्ती परीक्षा 23 को

रायपुर। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा छात्रावास अधीक्षक एवं अधीक्षिका के पदों पर भर्ती परीक्षा रविवाार 23 जुलाई को सुबह 10 से दोपहर 12=15 बजे तक जिले के निर्धारित 29 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। जिसमें जिले के 11 हजार 804 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उक्त परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु डिप्टी कलेक्टर एवं परीक्षा प्रभारी अधिकारी श्रीमती रूचि शर्मा को नोडल अधिकारी और सहायक संचालक कौशल विकास विभाग श्री केदार पटेल को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

सरकारी जमीन पर कब्जा कर बना रहा था मकान, निगम ने तोड़ा

रिसाली। प्रगतिनगर वार्ड 23 में निगम की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। दरअसल वामिनि देवेन्द्र जोशी खाली भूमि को अपना बताकर उस पर निर्माण कार्य शुरू की थी। जांच में निर्माण स्थल निगम के क्षेत्राधिकार का होना पाया गया। मुहल्ले के लोगो ने निगम आयुक्त आशीष देवांगन से शिकायत की थी कि वामिनि जोशी स्वयं की जमीन को सुरक्षित कर खाली जमीन पर मकान निर्माण कर रही है। शिकायत मिलते ही निगम के राजस्व विभाग प्रभारी संजय वर्मा ने जांच पूर्ण होने तक निर्माण कार्य बंद करने नोटिस जारी किया था। पटवारी प्रतिवेदन में स्पष्ट हुआ कि जमीन आयुक्त नगर पालिक निगम रिसाली के नाम पर है। सीमांकन रिपोर्ट मिलते ही निगम का अमला प्रगतिनगर पहुंचकर अतिक्रमण को हटाया। मकान बनाने वामिनि जोशी ने निगम कार्यालय के भवन अनुज्ञा शाखा से दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुमति ली थी। निगम ने वामिनि को खसरा नं. 184 पर निर्माण कार्य करने अनुमति दी थी, लेकिन भूमि स्वामी ने खसरा नं 183 पर निर्माण कार्य करा रही थी। आयुक्त ने निर्देश दिए है कि निगम की जमीन को चिन्हित किया जाए। सूची बनाने के बाद खाली जमीन पर पहले बोर्ड लगाए फिर उसे कटीले तार से घेर कर सुरक्षित करे।

छत्तीसगढ़ में भाजपा का जंगी प्रदर्शन

■ **विधायकों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार के खिलाफ लगातार धरना और प्रदर्शन के बाद बुधवार की दोपहर को बीजेपी ने उत्तर विधानसभा में व्याप्त बदहाली को लेकर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के उत्तर विधानसभा के विधायक कुलदीप जुनेजा के खिलाफ नारेबाजी भी की। बीजेपी नेताओं ने कानून व्यवस्था और घोटालों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच थोड़ी बहुत झूमाझटकी भी देखने को मिली।

17 बिंदुओं पर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन- बीजेपी नेताओं ने उत्तर विधायक कुलदीप जुनेजा के खिलाफ 17 बिंदुओं का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। जिसमें रायपुर उत्तर विधानसभा में सड़क डामरीकरण में हुए घोटालों की जांच, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप, लोकायुक्त की जांच पर कार्यवाही, विधानसभा के 5 वार्डों से निकलने वाले नाले

में हुए अधूरे निर्माण कार्य, अमृत मिशन के अधूरे काम, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा, अवैध शराब के साथ ही भू माफिया के द्वारा अतिक्रमण जैसे 17 बिंदुओं की जांच की मांग कलेक्टर से की गई है।

कोंडागांव में भी प्रदर्शन- बीजेपी के पांचों मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं दोनों विधानसभा में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्रीनिवास राव मद्दी, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य लता उसेंडी, संजय पाण्डेय, जिला अध्यक्ष दीपेश अरोरा के सामूहिक नेतृत्व में बड़ी संख्या कार्यकर्ता विधायक निवास घेरने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में विधायक से विधानसभा के विकास के नाम पर आए पैसों के दुरुपयोग पर सवालों की तख्तियां और बैनर पोस्टर थे। इस दौरान प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए।

स्थानीय मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन- स्थानीय मुद्दों जिनमें मक्का प्रसंस्करण इकाई के नाम पर किसानों के साथ छलावा, सड़क बायपास के नाम पर राजनैतिक लाभ लेकर झूठ परोसना, स्टेडियम और अन्य अधूरे निर्माण कार्य, सुराजी ग्राम योजनांतर्गत नरवा, गरुआ, घुरूवा और बाड़ी सहित गौठान में हुए भ्रष्टाचार, महिला स्व सहायता समूहों, बेरोजगारों, उद्यमियों को पर्याप्त साधन, समाधान और मार्गदर्शन दिये बिना बेतरतीब कर्ज बांटकर झूठी वाहवाही बटोरना शामिल था।

रामविचार नेताम ने भी बृहस्पति सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा- बलरामपुर के संयुक्त जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने कद्दावर बीजेपी नेता रामविचार नेताम के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर कुशासन और वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास जमा हो गई। रामविचार नेताम ने इस दौरान एसडीएम को ज्ञापन सौंपा ।पूर्व गृहमंत्री रामविचार नेताम ने प्रदेश कांग्रेस की सरकार और विधायक बृहस्पति सिंह पर आरोप लगाया। नेताम के मुताबिक विधायक फर्जी मुकदमे दर्ज कराते हैं जमीनों के फर्जी पट्टे बनवाते हैं।

बस्तर भी सरकार के खिलाफ हुआ एकजुट- वहीं जगदलपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र शुरू होते ही आदिवासियों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के विरोध में नग्न प्रदर्शन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेता कमल भंजदेव समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक और कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस की सरकार ने 36 वादे किए थे। जिनमें किसान, स्व सहायता समूह, शराबबंदी जैसे गंभीर विषय शामिल थे।कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ में साढ़े 4 साल पूरे हो चुके हैं और कांग्रेस ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। साथ ही जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में भी काम नहीं हुए हैं। जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्टर के माध्यम से गवर्नर को ज्ञापन सौंपा है।

मणिपुर से छत्तीसगढ़ की तुलना प्रदेश का अपमान है: भूपेश

■ **मणिपुर की घटना से ध्यान भटकाना इनका मकसद है**

रायपुर। मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने एक बार भी इस बारे में एक वक्तव्य नहीं दिए। उन्होंने इस मामले में 36 सेकेंड में अपनी बात कह दी। उन्होंने मणिपुर के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ को इसमें लपेट दिया। मणिपुर से छत्तीसगढ़ की तुलना प्रदेश का अपमान है। छत्तीसगढ़ दौरे पर पिछले दिनों आए पीएम मोदी व अमित शाह ने कभी कानून-व्यवस्था की बात नहीं की। मणिपुर की घटना से ध्यान भटकाना इनका मकसद है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मणिपुर में महिला को निर्वस्त्र घुमाया गया, बलात्कार हुआ। पूरा देश इस मामले में चिंतित है, लेकिन

प्रधानमंत्री ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। छत्तीसगढ़ दौरे में आए थे। चुनावी दौरे पर साढ़े 4 साल में पहली बार आए, लेकिन उनके भाषण में कहीं भी एक बार भी कानून-व्यवस्था को लेकर बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि अमित शाह कई बार आ चुके हैं, कानून-व्यवस्था के बारे में कोई बात नहीं कही। अचानक आज चूंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव है, इन दोनों को मणिपुर के साथ तुलना किए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई हालात या परिस्थिति नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कैसे अदालत में हत्याएं हो रही है, अस्पताल में हत्याएं हो रहे हैं। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में आदिवासियों के साथ अनुसूचित जातियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं।

बघेल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को विदेश जाने और चुनाव प्रचार करने से फुरसत नहीं है। प्रधानमंत्री पद में बैठे व्यक्ति के द्वारा ऐसे मनगंढ़त आरोप लगाया जाए और छत्तीसगढ़ की मणिपुर के साथ जोड़ा किया जाए। जबकि दोनों प्रदेश की कोई तुलना नहीं हैं। वे विदेश भ्रमण कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी मणिपुर नहीं गए। वहां की सरकार से कोई बात नहीं की और न ही कोई कार्रवाई की। मणिपुर की घटना अलग प्रकार की घटना है, लेकिन वे इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। मणिपुर की घटना से नाम जोड़कर छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है।पीएम जुमलेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी हर जगह हिंसा फैलाना चाहती है।

रायपुर में नग्न प्रदर्शन करने वाले हैं बड़े आरोपी

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नग्न प्रदर्शन करने वालों में से कई लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। रायपुर पुलिस ने ऐसे 5 आरोपियों का कच्चा चिट्ठा निकाला है जिनके खिलाफ बिलासपुर में हत्या, लूट, धोखाधड़ी मारपीट और बलवा का केस दर्ज है। पांच आरोपियों के नाम वेंकटेश मनहर, विक्रम जांगड़े, संजीत बर्मन, अमन दिवाकर, आशुतोष जानी है। पांचों बिलासपुर के रहने वाले हैं।

आरोपियों के नाम और उनपर दर्ज केस-आरोपी वेंकटेश मनहर निवासी जरहाभाटा जिला बिलासपुर के खिलाफ बिलासपुर के सिविल लाइन थाना में साल 2021 में धारा 147, 148, 149, 341, 294, 323, 506, 307, 397 और 120 बी के तहत मामला दर्ज है।

आरोपी विक्रम जांगड़े निवासी जरहाभाटा जिला बिलासपुर के खिलाफ बिलासपुर के सिविल लाइन थाना में साल 2011 में धारा 294, 506, 323, 34 साल 2020 में धारा 294, 323 506, 427 और 34 के तहत मामला दर्ज है। साल 2022 में धारा 147, 419, 420, 447 और 448 का मामला दर्ज है।

आरोपी संजीत बर्मन निवासी शांति नगर जिला बिलासपुर के खिलाफ बिलासपुर के सिविल लाइन थाना में साल 2011 में धारा 147, 294, 506, 427 और साल 2022 में धारा 295 ए 509 ख और आईटी

67 के तहत मामला दर्ज। आरोपी अमन दिवाकर निवासी जरहाभाटा जिला बिलासपुर के खिलाफ बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में साल 2021 में धारा 147, 148, 149, 340, 294, 323, 506, 307, 397, 120 बी के तहत मामला दर्ज है।

आरोपी आशुतोष जानी निवासी जरहाभाटा जिला सिविल लाइन के खिलाफ बिलासपुर के सिविल लाइन थाना में साल 2022 में धारा 147, 294, 323, 506, 427 के तहत मामला दर्ज है।

क्यों लगाई बिना कपड़ों के दौड़- फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार को कुछ युवाओं ने विधानसभा तक नग्न प्रदर्शन किया था। सभी युवक एससीएसटी के थे। पुलिस ने सभी 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। राजधानी में युवकों के नग्न प्रदर्शन पर बुधवार को विधानसभा के मानसून सत्र में जमकर हंगामा किया था।

हजारों जोगी कांग्रेसियों ने घेरा विधानसभा

■ **जो लोग सोच रहे थे पार्टी खत्म हो गई वे देख ले**

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य की एकमात्र मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय राजनीतिक दल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के द्वारा आज राजधानी रायपुर में वादाखिलाफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मुद्दों में जबरदस्त विधानसभा घेराव किया गया। जिसमें प्रदेशभर के कोने कोने से हजारों की संख्या में जोगी कांग्रेसियों ने भाग लिया और अमित जोगी के नेतृत्व में विधानसभा घेराव करने के लिए निकल पड़े। इस दौरान विधानसभा को घेरने के लिए निकले हजारों जोगी कांग्रेसियों को पुलिस ने पंडरी के पास बैरिकेट्स लगाकर रोक लिया। जोगी कांग्रेसियों संख्या को देखते हुए पुलिस ने डबल बेरिकेड्ट लगाए । इस दौरान जोगी कांग्रेसी और पुलिस के बीच जमकर झूमे छुटकी हुई जिसमें कई जोगी कांग्रेसी भी घायल हुए जिसमें प्रमुख रुप से अजीत जोगी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू को सीने में, नवल राठिया को घुटने में चोट लगी जिसका ईलाज अंबेडकर अस्पताल में चल रहा है वहीं संभागीय अध्यक्ष अश्वनी यदु का पैर फैक्चर हो गया। विधानसभा घेराव करने

से पूर्व पार्टी अध्यक्ष अमित जोगी ने पंडरी बस स्टैंड में सभा को संबोधित करते हुए कहा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेसी कांग्रेस में छत्तीसगढ़ को लूटने और वादाखिलाफी का प्रतियोगिता चल रहा है । 15 साल भाजपा ने लुटा साढ़े चार साल कांग्रेस लूट चुकी है। 15 साल बाद भाजपा बीमारी से निजात मिली थी वहीं प्रदेश में कांग्रेस का वायरस हो गया। जिस प्रकार वायरस शरीर को खोखला करता है वैसे ही कांग्रेस वायरस एटीएम बंद कर छत्तीसगढ़ को खोखला करने की काम कर रही है उन्होंने कहा भाजपा और कांग्रेस टॉम और जेरी की तरह लड़ रही है और आपस में नूरा कुश्ती कर रही है। अमित जोगी ने कहा जो लोग यह कहते थे कि जोगी की पार्टी खत्म हो गई वह आज देख ले की अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो यह अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है । अमित जोगी ने प्रदेश कांग्रेस को सभी मोर्चों पर फेल बताते हुए कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं । अमित जोगी ने जोगी पार्टी को लेकर समय-समय पर विलय करने की सवाल पर कहा जोगी पार्टी का विलय किसी भी दल के साथ नहीं हो सकता चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो या बीआरएस क्योंकि जोगी पार्टी का विलय छत्तीसगढ़ की जनता के साथ पहले ही हो चुका है। उन्होंने प्रदेश मुखिया श्री भूपेश बघेल की तुलना गजनी फिल्म के आमिर खान से करते हुए कहा उस फ़िल्म में आमिर ख़ान को भूलने की बीमारी होती है। वे सारी बातें दस-पंद्रह मिनट में भूल जाते थे। अपनी इस बीमारी के कारण, चीज़ों को याद रखने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर सारी ज़रूरी बातें टैटू करवा ली थी, लगता है मुख्यमंत्री' जी को भी अपने चुनावी वादे टैटू करवाने पड़ेंगे, उसके बिना उन्हें कुछ याद नहीं आएगा।उन्होंने कहा मैं आज श्री भूपेश बघेल जी से अपील करता हूँ कि अब भी समय है, अपने पापों का प्रायश्चित कर लें और हथकड़ी पहन कर अपने आप को छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के समक्ष सरेंडर कर दें।

गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण है अनिवार्य: डॉ.मिथिलेश

रायपुर। नियमित टीकाकरण के सुदृढीकरण के लिए जिला स्तरीय नियमित टीकाकरण पर कार्यशाला का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य नियमित टीकाकरण के विभिन्न पहलुओं को मजबूत करते हुए बेहतर सेवा को प्रदान करना था। कार्यशाला के अध्यक्षीय उद्बोधन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी ने कहा, जिस प्रकार मजबूत इमारत बनाने से पहले उसकी नींव को मजबूत किया जाता है, उसी प्रकार टीकाकरण शिशु के दुनिया में आने से पहले शुरू हो जाता है। एक स्वस्थ नागरिक बनाने के लिए गर्भवती महिलाओं का नियमित टीकाकरण किया जाना बहुत जरूरी होता है। टीकाकरण को सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ यह भी ध्यान रखना है कोई भी महिला टीकाकरण से ना छूटे । विशेष रुप से जन्म के बाद बच्चे का नियमित टीकाकरण अनिवार्य रूप से पूर्ण हो तभी हम स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला की जानकारी देते हुए, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. प्रीति नारायण ने बताया नियमित टीकाकरण के सुदृढीकरण तथा डिजीटलाईजेशन करने के लिए भारत सरकार और यूएनडीपी के द्वारा, यू-विन पोर्टल प्रारंभ किया गया है,जिसके अंतर्गत नियमित टीकाकरण के सत्र की प्लानिंग एवं सत्र का क्रियान्वयन टीकाकरण रिपोर्टिंग, टीकाकरण पश्चात सर्टिफिकेट लाभार्थियों का ड्यू लिस्ट तैयार करना यू-विन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन से किया जाना है। गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण का डिजिटलीजेसन के मुख्य उद्देश्य से यू-विन कार्यक्रम की शुरूआत की गई।

विधानमण्डल सदस्य निरर्हता निवारण संशोधन विधेयक सदन में पारित

■ **चर्चा के दौरान विपक्ष ने टेकाम के जरिए सरकार पर साधा निशाना**

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ विधानमण्डल सदस्य निरर्हता निवारण संशोधन विधेयक पारित हुआ. विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ. एक ओर विपक्ष ने प्रेमसाय सिंह टेकाम के जरिए सरकार पर निशाना साधा, वहीं विधायक धर्मजीत सिंह की टिप्पणी पर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों में तीखी बहस छिड़ गई.

सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा और अजय चंद्राकर ने कहा कि डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम में जरा भी स्वाभिमान है, तो उन्हें योजना आयोग अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं करना चाहिए. क्योंकि उनके लिए संसोधन विधेयक लाया गया. क्या ऐसी स्थिति में भी इस पद को टेकाम स्वीकार करेंगे? मुझे लगता है टेकाम की बलि ले ली गई. टीएस सिंहदेव के एक मात्र समर्थक की शहादत हो गई है.

शिवरतन शर्मा ने कहा कि सत्र की अधिसूचना के

बाद आप सत्र के बाहर घोषित कर सकते हैं क्या? इस संशोधन को लाने का प्रमुख कारण इनका आंतरिक कलह है. साल भर से सीएम लगे हुए थे कि मोहन मरकाम दूर हो जाएं. सीएम लगातार प्रयास करते रहे कि उनको अध्यक्ष से हटाया जाए. सशर्त अनुमति मिल गई कि उनको हटाया जाए तो डिप्टी सीएम बना दिया गया. राजा साहब के करीबी प्रेमसाय की राजनीतिक शहादत हो गई. आपके नेता जी की साढ़े चार साल दुर्गति हो गई. उसी दुर्गति को आपको प्राप्त करना है, तो हमारी शुभकामना है. यदि थोड़ा भी स्वाभिमान हो तो पद को नहीं लेना चाहिए.

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि हम यहां कानून बनाने जा रहे हैं. क्या मुख्यमंत्री सदन से बड़े हैं. यह सदन का अपमान है. लोकतंत्र का अपमान है. सदन से बड़ा कोई नहीं है. हमारे सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है. क्या कोई सदन के बाहर घोषणा कर सकता है क्या? विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि वो आदमी जो 45 साल पहले मंत्री थे और जिस बेरहमी से उनको निकला गया, लॉलीपॉप खिलाना था तो इत्मीनान से खिलाते. प्रेम साय सिंह के चेहरे से नूर छीन लिए हैं. रात में आप से इस्तीफा लिया गया और आप सुबह अपने क्षेत्र के लिए निकल गए थे. बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि जो साढ़े चार साल नंबर दो थे, अचानक उनको खिसका दिया गया.

विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ. विधायक धर्मजीत सिंह की टिप्पणी पर सत्तापक्ष के आदिवासी विधायक भड़क गए थे. धर्मजीत सिंह पर सत्ता पक्ष के विधायक बृहस्पत सिंह ने जातिगत रूप टिप्पणी करने का आरोप लगाया. इस पर धर्मजीत सिंह ने कहा कि मैंने किसी जाति को लेकर कोई बात नहीं कही. मैंने सिर्फ नग्न प्रदर्शन की बात कही है. धर्मजीत सिंह ने कहा कि रिकॉर्ड चेक करा लिया जाए. जातिगत टिप्पणी की होगी तो मैं विधायकी से इस्तीफ़ा दे दूंगा.

अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आसंदी ने पहले व्यवस्था दी हुई है. इस सदन में सभी विधायक समान हैं. जाति से ऊपर हैं. नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सदन में टिप्पणी व्यक्तिगत होती है ना कि जातिगत. इस मामले में आसंदी की व्यवस्था होनी चाहिए. संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि धरमलाल कौशिक को किस दुर्गति से नेता प्रतिपक्ष पद से हटा दिया गया. क्या हमने ये नहीं देखा है? आदिवासी दिवस के दिन इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया. क्या हमने नहीं देखा? कहने को हमारे पास भी बहुत कुछ है.

मंत्री डहरिया और बृजमोहन के बीच सदन में तीखी बहस

■ रायपुर में विकास कार्य के मुद्दे पर बवाल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में विकास कार्य के मुद्दे पर सवाल पूछे। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा कि रायपुर में केंद्र सरकार ने कितना पैसा दिया और कितना शहर के विकास में खर्च हुआ? मंत्री शिव डहरिया ने बृजमोहन अग्रवाल के सवाल का जवाब दिया, जिसके बाद सदन में तीखी बहस हुई।

मंत्री डहरिया ने दिया ये जवाब

भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल के रायपुर में विकास कार्य के सवाल पर मंत्री डहरिया ने जवाब दिया कि 1327 करोड़ 49 लाख रुपए 32 हजार रुपए की राशि मिली है। कुल 9615 कार्य स्वीकृत हुए हैं। ज्यादातर काम पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास का काम बाकी है। इसका सर्वे बीजेपी शासनकाल में हुआ। सर्वे में गलती थी, इसलिए प्रधानमंत्री आवास का काम बाकी है। इसके अलावा ज्यादातर काम शुरू हो गए हैं और ज्यादातर काम पूरे भी हो गए हैं।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राजधानी रायपुर की पिछले साढ़े चार साल में बुरी हालत हो गई है। अग्रवाल

ने कहा कि राजधानी की स्थिति खराब है। यहां मुगलिया शासन चल रहा है और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है।

बृजमोहन ने यह सवाल भी पूछा कि तेलीबांधा रोड पर सौंदर्यीकरण किसने किया? मंत्री डहरिया ने कहा, हमें नहीं पता।

बृजमोहन ने पूछा आठ साल में कितने पत्र लिखे बता दीजिए, सड़क चौड़ीकरण का मसला है। ये चला चली की बेला है। मंत्री ने जवाब दिया कि तात्यापारा की सड़क पीडब्ल्यूडी से बन रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने यह तक कहा कि मंत्रीगण ज्ञान की परीक्षा ना लें, किस मद से पैसे खर्च किए, यह बताएं ? सीएम भूपेश ने जो दस करोड़ की घोषणा की, वो क्या है ?

बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि आप केवल यह बता दीजिए 9615 काम स्वीकृत किए, इसमें कितने काम पूरे हैं और कितने अधूरे हैं। केवल घोषणा कर देने से कुछ नहीं होता है। शारदा चौक से तात्यापारा के चौड़ीकरण की मांग की गई है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन विभाग में 10 करोड़ की घोषणा की है, वह किस बजट से किए हैं, वह भी बता दें।

बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि रायपुर की स्थिति बहुत खराब है और मंत्री जी की रायपुर में कुछ नहीं चलती। मंत्री ने कहा कि वहां स्थिति यह है कि छह करोड़ का काम है और 80 करोड़ देना है। मंत्री डहरिया ने कहा कि तात्या पारा की सड़क का बजट पीडब्ल्यूडी में शामिल हो गया है।

अग्रवाल ने कहा कि वह काम पीडब्ल्यूडी को नहीं नगर निगम को करना है। उस सड़क के लिए 40 करोड़ चाहिए लेकिन सीएम ने केवल 10 करोड़ की घोषणा की है तो सड़क कैसे बनेगी? अग्रवाल ने आरोप लगाया कि रायपुर से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। डहरिया ने कहा कि हमने रायपुर ही नहीं पूरे प्रदेश के शहरों को संवारा है। पीएम आवास में सबसे बड़ा पुरस्कार हमें मिला है। हम काम अच्छा कर रहे हैं।

फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के सहारे नौकरी करने वालों को बर्खास्त करने के निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र मामले में सरकार सख्त रुख अपना लिया है. मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने 16 विभाग के अधिकारियों की बैठक ली. फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे नौकरी करने वालों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं.मुख्य

सचिव अमिताभ जैन ने विभागीय अधिकारियों से अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली. फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे नौकरी करने वालों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कोर्ट में लंबित प्रकरणों में जल्द सुनवाई पर जोर दिए जाने समेत विभागों में लंबित प्रकरणों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. गौरतलब है कि एससी-एसटी के युवाओं ने फर्जीवाड़ा मामले में नग्न प्रदर्शन किया था.

नानघाट से बलौदा बाजार सड़क निर्माण की लागत पर चर्चा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीसरे दिन की कार्यवाही हुई। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रॉस्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट सदन में

रखी। जिस पर चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक शिवरतन शर्मा ने नानघाट से बलौदा बाजार सड़क निर्माण की लागत का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इस 5वीं विधानसभा में चौथी बार ये प्रश्न लगाया है। इस सड़क में 13 से 14 किलोमीटर की सड़क बैठ गई है। लोक निर्माण मंत्री ताम्र ध्वज साहू ने कहा कि सड़क की स्थिति संतोषजनक है। इस पर विधायक ने आपत्ति जताई।

नानघाट से बलौदा बाजार सड़क निर्माण की लागत पर चर्चा- शिवरतन ने पूछा कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र को कार्यवाही करने का अधिकार है क्या। मंत्री ने कहा कि कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है। कुछ जगह सुधार के लिए कहा गया है। शर्मा ने कहा की केंद्र ने जब अनियमितता की बात कही है तो आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि हम ठेकेदार के खर्च पर सुधार करवा रहे हैं। शर्मा ने आरोप लगाया कि ठेकेदार को बचाने की कोशिश की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की स्थिति दयनीय है। इस सड़क की वीडियोग्राफी कर जांच कराने की मांग की। मंत्री ने कहा कि हम दिखवा लेंगे।

खाद्यान्न योजना में अनियमितता का मामला उठा, मंत्री भगत ने दिया जवाब

विधानसभा में गुरुवार को खाद्यान्न योजना में अनियमितता का मामला उठा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमनसिंह द्वारा विधानसभा में पूछे गये प्रश्न का जवाब देते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने विधानसभा में बताया

कि राज्य शासन को बदनाम करने के लिए मनगढंत आरोप लगाया गया है। डॉ रमन सिंह द्वारा प्रेषित पत्र के पूर्व में केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय को दो पत्र लिखे उसमें 12 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत माह अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक कुल 33 माह के हिसाब से केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को 38 लाख टन चावल का आबंटन देना बताया जबकि केन्द्र सरकार से 28 माह के लिए 28.10 लाख टन चावल का आवंटन प्राप्त हुआ है। डॉ. रमन सिंह द्वारा प्रेषित पत्र पर केन्द्र द्वारा जांच में भी असत्य पाया गया है, और इस तरह से आरोप पूरी तरह मिथ्या / मनगढंत व राजनीति से प्रेरित साबित होता है।

संविदा कर्मियों के आंदोलन पर हंगामा

रायपर। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन अनियमित और संविदा कर्मियों के आंदोलन के मुद्दे पर जमकर हंगामा हो गया। भाजपा विधायकों ने जमकर नारेबाजी की है। साथ ही स्थगन प्रस्ताव लाने की सूचना दी है। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने भूपेश है तो भरोसा है के नारे लगाये।

विपक्ष की ओर से मोर्चा संभाल रहे अजय चंद्राकर ने मुख्यमंत्री को कहा आई लव यू तो आसंदी समेत पूरा सदन हंसी के ठहाके से गूंज उठा। दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग व सड़क की गुणवत्ता को लेकर विधायक शिवरतन सवाल कर रहे थे। इसमें संतोषप्रद शब्द का उल्लेख था तब चंद्राकर ने प्रतिप्रश्न किया कि यह संतोषप्रद क्या होता है? इसी बीच सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे तो चंद्राकर ने उन्हे नमस्ते किया तो वे मुस्कुराकर अपनी सीट पर बैठ गए। फिर जब सदन में चंद्राकर के बोलने की बारी तो वे ऊंची आवाज में बात करने लगे जिससे अध्यक्ष महंत ने चुटकी लेते हुए कहा कि क्या बात है जब तक सीएम नहीं आए थे आप संतोषप्रद ढंग से सवाल कर रहे और उनके आते ही तेज हो गए।

चंद्राकर ने कहा नहीं ऐसा नहीं हैं हमने लखमा के लिए आईलवयू कहा था अब मुख्यमंत्री जी के लिए भी आईलवयू कहते हैं तो पूरा सदन हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। तब मुख्यमंत्री भी भला कहां चूकने वाले थे उन्होने कहा कि मतलब मैं चंद्राकर जी के लिए उत्प्रेरक का काम करता हूं। फिर हंसी छूट गई।

राशन घोटाला में पर्दा डालने का काम कर रही हैं सरकार: कौशिक

रायपुर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि पिछले सत्र में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा राशन दुकानों के भौतिक सत्यापन को लेकर 24 मार्च 2023 को कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात की गई थी। श्री कौशिक ने कहा कि खाद्य मंत्री ने इस बात को तो स्वीकार कर लिया है कि अनियमितता पायी गई है और अनियमितता पाये जाने के बाद में जिस प्रकार से कार्यवाही होनी चाहिए जिसके विषय पर उन्होंने उच्च न्यालय का हवाला दिया कि न्यायालय में 34 याचिकाएं लगायी गयी है लेकिन उस याचिका के लगाने के बाद में

उच्च न्यायालय द्वारा क्या निर्देश दिया गया जिससे इस पर जांच नहीं हो सकती। इसकी जानाकारी खाद्य मंत्री नहीं दे पा रहे है, न ही जवाब नहीं दे पा रहे। उन्होंने कहा कि सरकार केवल अपने जवाब से बचना चाह रही है और घोटालों पर पर्दा डालने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक में जब भाजपा ने 5100 करोड़ रू का राशन घोटलों को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाया था तब यह सामने आया कि रायपुर, बिलासपुर व अंबिकापुर में जिस प्रकार से दुकानों को निलंबित किया गया है जिससे यह मामला प्रमाणित हो गया कि प्रदेश में बड़े स्तर पर राशन घोटला किया गया है और इसको लेकर के जवाब देना न पड़े इसी कारण कि खाद्य मंत्री ने उच्च न्यायालय का हवाला दिया और जवाब से बचते रहे। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपने जवाब से बचते रहेंगे और घोटलों पर पर्दा डालने का काम करेंगे? क्योंकि जब से कांग्रेस की यह सरकार प्रदेश में आयी है लगाता हर विभाग हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और घोटला हुआ है जो एक-एक करके सामने आ रहा है इसी तरह राशन में भी बड़े स्तर पर घोटला हुआ है जो कि साबित हो रहा है।

राज्यपाल श्री हरिचंदन नई दिल्ली में आयोजित इंडियन रेडक्रास की बैठक में शामिल हुए

रायपुर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु की अध्यक्षता में गत दिवस राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में इंडियन रेडक्रास सोसायटी की वार्षिक सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई जिसमें राज्यों के राज्यपाल और रेडक्रास समिति के पदाधिकारी उपस्थित थें। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में रेडक्रास सोसायटी के पिछले वर्षो के आय व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रेडक्रास समितियों और रेडक्रास स्वंय सेवकों को सम्मानित किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ रेडक्रास सोसायटी के सी. ई. ओ. श्री एम. के. राउत, चेयरमैन श्री अशोक अग्रवाल एवं समिति के सचिव डॉ. रूपल पुरोहित भी उपरिथत थें।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य के लोगों का अपमान किया : बैज

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मणिपुर के हालात से छत्तीसगढ़ को तुलना किये जाने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति व्यक्त किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर से छत्तीसगढ़ की तुलना कर

छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान किया है। मणिपुर जातीय और वर्ग संघर्ष में जल रहा केंद्र सरकार भाजपा की मणिपुर सरकार वहां के हालात को सुधारने में पूरी तरह नाकामयाब साबित हुई है। छत्तीसगढ़ में शांति और खुशहाली की स्थिति है। छत्तीसगढ़ में सभी धर्म जाति और संप्रदाय के लोग आपसी भाई चारे के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुये शांतिपूर्ण ढंग से निवासरत है। प्रधानमंत्री के बयान से उनकी बौखलाहट झलक रही है मणिपुर संभल नहीं रहा तो देश के शांतिपूर्ण राज्यों से उसकी तुलना कर प्रधानमंत्री अपनी खीझ निकाल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री मतिभ्रम के शिकार हो गये हैं। उन्हें ऐसा लग रहा छत्तीसगढ़ में अभी भी रमन सिंह के कुशासन का राज है। वे भूल गये है कि छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के कुशासन का दौर समाप्त हो गया है, जब छत्तीसगढ़ में मीना खल्खों, झलियामारी, हिड़मा मड़कम जैसे कांड होते थे। भाजपा के पन्द्रह साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ महिलाओं के लिये सबसे ज्यादा असुरक्षित हो गया था।

विजय बघेल की हैसियत नहीं कि वो सीएम को चैलेंज करे: ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गेड़ी दौड़ की चुनौती देने के पहले विजय बघेल अपनी राजनैतिक हैसियत को देखें, अभी वे इतने बड़े नहीं हुये है कि वे मुख्यमंत्री को चुनौती दें। गेड़ी चढ़ने की चुनौती रमन

सिंह को दी गयी रमन सिंह इस चुनौती पर क्यों मौन हैं? प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रमन सिंह घबराकर विजय बघेल को आगे कर रहे है। गेड़ी चढ़ना हो तो विजय बघेल, चुनाव जीतने मूंछ दाव में लगाना था तो कुंवर दिलीप सिंह जूदेव और 15 साल तक सत्ता की मलाई खाये डॉ. रमन सिंह और उनके परिजन। यही भाजपा का छत्तीसगढ़ियाँ विरोधी चरित्र है। 15 साल में कभी विजय बघेल को भी भाजपा कार्यालय में गेड़ी चढ़ते नही देखा, न गेड़ी दौड़ कराते सुना। विजय बघेल छत्तीसगढ़ियाँ है उन्हें छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा, तीज-त्यौहार, रहन-सहन, खान-पान, बोली, भाषा का ज्ञान है। पर वो 15 साल के रमन सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ संस्कृति को दोयम दर्जे से देखने पर मौन क्यो थे? विजय बघेल 15 साल कुर्सी दौड़ में लगे थे उन्हें कभी गेड़ी की याद नही आई ऐसा क्यो? प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जो भाजपा के नेता कल तक कहते नहीं थकते थे कि वो छत्तीसगढ़ियावाद की बात नहीं करेंगे, वो आज अगर छत्तीसगढ़ियावाद की बात कर रहे, निभा रहे तो यह भूपेश सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

भाजपा का कर्मचारी विरोधी चेहरा सामने आ गया: शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने, संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि सहित सभी वर्गों को उदारतापूर्ण तरीके से लाभ

दिए जाने पर राज्य के कर्मचारी संगठन उनका अभिनंदन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके जीवन को खुशियों से भर दिया है तो विपक्ष का कलेजा फट रहा है। कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों, मजदूरों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं के जीवन में खुशहाली लाने के साथ लोक सेवकों का वेतन भत्ता बढ़ा दिया तो भाजपा में कोहराम मच गया। वह रुदन कर रही है। उसका कर्मचारी विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सरकारी सेवकों के हित में बड़े फैसले लिए तो भाजपा को यह नागवार गुजरा। उसके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि राज्य के 5 लाख कर्मचारी मुख्यमंत्री बघेल की जिंदाबाद करने लगेंगे। भाजपा ने 15 साल कर्मचारियों का शोषण किया और अब चुनाव नजदीक आते ही उन्हें भड़काने की साजिश कर रही थी। भाजपा की सारी साजिश कांग्रेस सरकार ने विफल कर दी है।

अजा और जजा के लोग कभी माफ नही करेंगे : साय

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष द्वय विष्णुदेव साय व विक्रम उसेंडी, पूर्व सांसद रामविचार नेताम, पूर्व मंत्री डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, महिला मोर्चा राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य लता उसेंडी, अनुसूचित

जनजाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कण्डेय ने कहा है कि प्रदेश सरकार के खिलाफ युवाओं का पूर्णतः नग्न प्रदर्शन छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली घटना है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ युवाओं का आक्रोश अब इस स्तर तक पहुँचकर फूटा है! अपने संयुक्त वक्तव्य में भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ और पूरे देश में ऐसा प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ। क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यही छत्तीसगढ़ियावाद है कि छत्तीसगढ़ के युवा अपने न्याय और हक की लड़ाई के लिए निर्वस्त्र होकर सड़कों पर दौड़ें? भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार ने यदि समय रहते फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी के इन मामलों में कार्रवाई की होती तो छत्तीसगढ़ महतारी के युवा पुत्रों को इस तरह शर्मनाक प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आती। आज छत्तीसगढ़ महतारी शर्मिन्दा है कि उसकी औलादों को निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करना पड़ा। युवाओ के इस प्रदर्शन में वस्तुत- युवा नग्न नहीं हुए हैं, बल्कि प्रदेश की जनता के सामने पूरी राज्य सरकार ही नंगी हो गई है।

एक और चिटफंड कंपनी की सम्पत्ति होगी कुर्क

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई तेजी से जारी है। एक और चिटफंड कंपनी वेल्थ क्रियेटर एण्ड रूचि रियल स्टेट की रायपुर के बीरगांव स्थित लगभग सवा दो एकड़

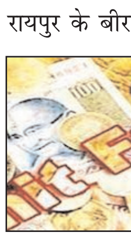

जमीन की कुर्की का निर्देश जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने जारी किया है। कंपनी के खिलाफ सम्पत्ति कुर्की का यह निर्देश छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। चिटफंड कंपनी की संपत्ति के कुर्की से मिलने वाली राशि निवेशकों को लौटायी जाएगी। कंपनी के संबंध में निवेशकों द्वारा शिकायत दर्ज कराने पर पूरी जांच के बाद जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।कंपनी वेल्थ क्रियेटर एण्ड रूचि रियल स्टेट द्वारा सुनियोजित ढंग से कूटरचित दस्तावेजों से आमजनता को अधिक ब्याज देने, कम समय में धन दोगुना करने का झांसा देकर कई लोक लुभावनी योजनाएं बताकर निवेशकों से कपटपूर्ण ढंग से राशि जमा करायी गई। निवेशकों द्वारा जमा करायी गई राशि परिपक्वता के बाद भुगतान नहीं करने, जमा की गई राशि को वापस नहीं करने और जमा राशि का ब्याज भी अदा नहीं कर धोखाधड़ी की गई। इस संबंध में निवेशकों द्वारा कंपनी संचालकों के विरूद्ध कोरबा कोतवाली थाने में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था।

प्रस्तावित होलसेल कॉरिडोर के लिए व्यापारिक संघों की बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव,राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि नया रायपुर में 1000 एकड़ में प्रस्तावित होलसेल कारिडोर के लिये लैंडयूज बदला जा चुका है। होलसेल कारिडोर में स्थान लेने हेतु एनआरडीए (नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण) द्वारा जारी प्रारूप के अनुसार व्यवसायिक संघों को आवेदन प्रस्तुत करने कहा गया है जिसके परिपेक्ष्य में आज चेंबर भवन में छत्तीसगढ़ चेंबर अध्यक्ष श्री अमर पारवानी जी के नेतृत्व में प्रस्तावित, दक्षिण मध्य एशिया के सबसे बड़े होलसेल कॉरिडोर के लिए

आवेदनकर्ता विभिन्न व्यापारिक संघों के प्रमुखों के साथ बैठक का आयोजन किया गया जिसमे चेंबर के पदाधिकारीगण सहित बड़ी संख्या में व्यापारीगण भी उपस्थित रहे।चेंबर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर पारवानी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा स्वीकृत इस महती योजना एवं चेंबर का विजन अब जल्द ही मूर्त रूप लेने तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रस्तावित नए होलसेल कॉरिडोर की परिकल्पना से प्रदेश के समस्त व्यापारी भली भांति परिचित हैं।

श्री पारवानी ने आगे बताया कि प्रस्तावित होलसेल कॉरिडोर को लेकर एनआरडीए ''नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण'' द्वारा व्यवसायिक संघों के लिए उनके आवश्यकताओं के अनुरूप एक प्रपत्र जारी किया गया है जिसे व्यापारिक संघों के प्रमुखों द्वारा, जिन्होंने होलसेल कॉरिडोर में स्थान पाने हेतु आवेदन दिया है, उन्हें उक्त प्रपत्र अनुसार आवेदन मांगा गया जिन्हें चेंबर द्वारा व्यवसायिक संघों के प्रमुखों से भरवाया गया तथा उपस्थित व्यापारियों एवं संघ प्रमुखों को इस विषय से संबंधित विभिन्न जानकारी दी गई।बैठक में श्री मनीष पल्लीवार द्वारा होलसेल कॉरिडोर मॉडल को प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रतुत किया। यह होलसेल कॉरिडोर स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अटल नगर रेलवे स्टेशन निर्माणाधीन तथा भारत माला सड़क परियोजना एवं एनएच 30 के समीप होगा जो भौगोलिक रूप से हमारी सीमा से लगे उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश और झारखंड की मांग की आपूर्ति कर सकेगा तथा प्रदेश के व्यापार को नई ऊंचाई, दिशा और गति देगा।

यूपीएससी परीक्षा को लेकर टॉपर्स टॉक आज, युवाओं को मिलेंगे टिप्स

रायपुर। यूपीएससी सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए 21 जुलाई का दिन विशेष रहेगा। यूपीएससी परीक्षा के बारे में परीक्षार्थियों को पूरी जानकारी देने और उनके सवालों के समाधान के लिए रायपुर शहर में टॉपर्स टॉक का आयोजन हो रहा है। 21 जुलाई सुबह 10 बजे पं दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस टॉपर्स टॉक में वर्ष 2022 की यूपीएससी सिविल सर्विसेस परीक्षा के टॉपर्स प्रतिभागियों के बीच होंगे और अपने सफलता के अनुभव साझा करेंगे। 21 जुलाई को छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों को यूपीएससी की सिविल सर्विसेस परीक्षाओं के टॉपर्स से मिलने, बात करने का सुनहरा मौका मिलेगा। यूपीएससी परीक्षा में पहले तीन स्थानों पर चयनित टॉपर्स रायपुर आ रहें है।

यूपीएससी की 2022 सिविल सेवा परीक्षा की टॉपर इशिता किशोर के साथ सेकेण्ड टॉपर गरिमा लोहिया और नौवाँ स्थान प्राप्त करने वाली कनिका गोयल भी रायपुर आ रहीं हैं। साथ ही 2022 की परीक्षा में 17वीं रैंक पाने वाले अविनाश कुमार, छत्तीसगढ से सर्वोच्च रैंक पाने वाले अभिषेक चतुर्वेदी और 2021 की परीक्षा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित प्रखर चंद्राकर भी इन टॉपर्स के साथ रहेंगे।

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने इस बारे में बताया कि जिला प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर आईएएस, आईपीएस जैसे पदों पर चयनित होने की इच्छा रखने वाले परीक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए 21 जुलाई को टॉपर्स टॉक आयोजित की जा रही है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.